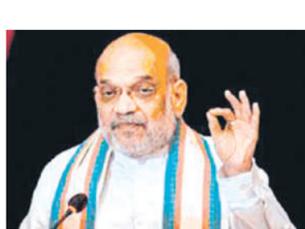




■ एम.ओ.एफ.एस.एल की रिपोर्ट के अनुसार सोने की चमक कायम रहने की उम्मीद - 10



■ सोशल मीडिया पोस्ट के साथ नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख जरूरी - 10



■ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बोले- बंगाल में गाजपा जीती तो घुसपैठियों पर कड़ा एवशन - 11



■ लय में लौटे घुरंघर, विस्फोटक पारियां खेल जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराया - 12

आज का मौसम **31.0°**
अधिकतम तापमान
16.0°
न्यूनतम तापमान
सूर्योदय 06.35
सूर्यास्त 06.09

आमृत विचार

एक सम्पूर्ण दैनिक अखबार

www.amritvichar.com

2 राज्य | 6 संस्करण

लखनऊ | बरेली | कानपुर | मुरादाबाद | अयोध्या | हल्द्वानी

शुक्रवार, 27 फरवरी 2026, वर्ष 36, अंक 23, पृष्ठ 12+4 | मूल्य 6 रुपये

‘द केरल स्टोरी 2’ पर रिलीज से एक दिन पहले लगी अंतरिम रोक

कोच्चि, एजेंसी

केरल हाईकोर्ट ने ‘द केरल स्टोरी 2-गोज बिगॉन्ड’ के प्रदर्शन पर बृहस्पतिवार को अंतरिम रोक लगा दी। फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी। न्यायमूर्ति बी. कुरियन थॉमस ने फिल्म के प्रदर्शन को चूनाती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि फिल्म सामाजिक सद्भाव को भंग न करे। हाईकोर्ट ने कहा, सीबीएफसी की ओर से प्रमाणन प्रदान करते समय कानून की स्पष्ट अवहेलना हुई है, अदालत ने कहा कि ऐसी सामग्री

● केरल हाईकोर्ट ने कल- फिल्म सामाजिक सद्भाव भंग न करे, ये कोशिश नहीं की गई

THE KERALA 2

का प्रसार, जिसमें वैमनस्य उत्पन्न करने, कानून-व्यवस्था भंग करने और यहां तक कि सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति हो, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) में निहित वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता है। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता श्रीदेव नंबूदरी की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को दो सप्ताह के भीतर विचार कर आदेश पारित करे।

‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ अध्याय वाली पुस्तक पर प्रतिबंध

एनसीईआरटी निदेशक और शिक्षा विभाग के सचिव को कारण बताओ नोटिस, आपराधिक अवमानना की कार्यवाही की चेतावनी

नई दिल्ली, एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की उस पुस्तक के भविष्य में किसी भी प्रकाशन, पुनमुद्रण या डिजिटल प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ नाम का खंड शामिल किया गया था। कोर्ट ने पुस्तक की सभी प्रतियां तुरंत ज्वब करने और डिजिटल प्रतियां हटाने का निर्देश दिया। एनसीईआरटी के निदेशक और शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर पूछा गया कि क्यों न अवमानना और दूसरी जरूरी कार्यवाही की जाए।

कोर्ट ने इस मामले में गहन जांच की मंशा जताते हुए स्पष्ट किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर गंभीर परिणामों

● उन बैठकों का मूल रिकॉर्ड तलब जिनमें अध्याय को विचार-विमर्श कर दी गई मंजूरी

और स्थाई प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा दुर्व्यवहार न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2(सी) के अंतर्गत आपराधिक अवमानना के दायरे में आएगा। यह जानबूझकर किया गया कृत्य पाया जाता है तो न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप के साथ संस्था को बंदनाम करने का भी मामला होगा। कोर्ट ने उन बैठकों के व्योरे का मूल रिकॉर्ड तलब किया, जिनमें आपत्तिजनक अध्याय पर विचार-विमर्श किया गया था और उसे अंतिम रूप दिया गया था।

न्यायपालिका के खिलाफ गहरी साजिश और सुनियोजित प्रयास: सीजेआई

सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से नाराज नजर आ रहे सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, पुस्तक की सामग्री के प्रथम दृष्टया अवलोकन और निदेशक से प्राप्त प्रशासनिक प्रतिक्रिया के साथ इसे पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक गहरी साजिश के तहत न्यायपालिका के संस्थागत प्राधिकार को कमजोर करने और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का एक सुनियोजित प्रयास किया गया है। सीजेआई ने कहा, उन्होंने आघात किया है। न्याय पालिका इससे आहत है। न्यायिक संस्था के प्रमुख के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं पता लगाऊं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुस्तक में शब्दों और अभिव्यक्तियों का चयन महज अनजाने में हुई गलती या त्रुटि नहीं हो सकता।

सुधारों का पुस्तक में नहीं किया जिक्र

शीर्ष अदालत ने उल्लेख किया कि पुस्तक में वर्णित विवरण न्यायालय द्वारा शुरू की गई किसी भी परिवर्तनकारी पहल और उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिनमें न्याय एक सुगम पहुंच को सुव्यवस्थित करना और लोकतांत्रिक तानेबाने के संरक्षण में न्यायपालिका का महत्वपूर्ण योगदान भी शामिल है। इस न्यायालय द्वारा अतीत में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के गहन आदि के लिए निंदा किए गए उच्च पदस्थ अधिकारियों की भारी संख्या को देखते हुए यह युष्पी विशेष रूप से निंदनीय है।

मामले में कार्रवाई की जाएगी: प्रधान

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मद प्रधान ने एनसीईआरटी की आठवीं की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर अध्याय शामिल करने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने जवाबदेही तय करने और पाठ्यक्रम के विवादास्पद अंश को तैयार करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया। प्रधान ने इस बात पर जोर भी दिया कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और इस संस्था का आनादर करने का उसका कोई इरादा नहीं है। जो कुछ हुआ है उससे मैं बहुत दुखी हूँ।

● पीठ ने कहा, पुस्तक में अत्यंत लापरवाही, गैरजिम्मेदाराना, अपमानजनक तरीके से लिखी बातों पर गौर करने के बजाय एनसीईआरटी निदेशक ने अपने जवाब में सामग्री का बचाव किया।

● पीठ ने कहा कि यदि यह बैरोकेटको होने दिया गया तो न्यायपालिका की श्रुति और आम लोगों के बीच उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी, इससे भी महत्वपूर्ण है कि बच्चों के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा।

ब्रीफ न्यूज

हवाई अड्डे पर 24 करोड़ का मादक पदार्थ जब्त

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने थाईलैंड से आते हुए यात्रियों के पास से 23.9 किलोग्राम सिंथेटिक मादक पदार्थ जबाब किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 24 करोड़ रुपये है।

आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक यात्री 22 फरवरी को टर्मिनल 3 पर पहुंचे जहां उन्हें आरक्षण क्षेत्र के ग्रीन चैनल पर रोका गया। उनके सामान की पहले एक्स-रे जांच और बाद में विस्तृत जांच की गई। तलाशी में हरे रंग के सिंथेटिक मादक पदार्थ से भरी पॉलीथीन की 14 थैलियां बरामद की गईं जिनमें से आठ एक ट्रॉली बैग में और छह दूसरे बैग में छिपाई गई थीं।

महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून का मसौदा तैयार

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कथित ‘लव जिहाद’ के मामले को रोकने के मकसद से प्रस्तावित कानून का एक मसौदा तैयार किया है। विधि एवं न्यायपालिका विभाग ने मसौदा कानून को अंतिम रूप दे दिया है। सतारुद दल के विधायकों की तरफ से जबरदस्ती, धोखाधड़ी या लालच देकर किए गए धर्म परिवर्तन को अपराध मानने के लिए एक सख्त कानून की मांग बढ़ रही थी। इससे जवाब में राज्य सरकार ने इस मामले की संवेदनशील प्रतिक्रिया को देखते हुए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई थी। कई भाजपा शासित राज्यों ने पहले ही धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बना दिए हैं।

राकांपा की अध्यक्ष बनीं सुनेत्रा पवार

मुंबई। महाराष्ट्र में उममुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का निर्वाचन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उनके बड़े बेटे पार्थ पवार को जल्द ही राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए जाने की संभावना है। यह आधिकारिक घोषणा वर्र्ग 2026 के दौरान की गई। राकांपा प्रमुख रहे अजित पवार के असामयिक निधन के बाद पार्टी की कमान संभालने के लिए सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने रखा, जिसे सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। पार्टी के नए अध्यक्ष सुनेत्रा पवार का प्रस्ताव वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे को शामिल किया गया है।

भारत-इजराइल के संबंधों का नया दौर विशेष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा

मोदी की यात्रा के दौरान कृषि, ऊर्जा और डिजिटल भुगतान के क्षेत्रों में 17 समझौते

● सैन्य उपकरणों के संयुक्त विकास और उत्पादन की दिशा में काम करेंगे दोनों देश

यरुशलम, एजेंसी

भारत और इजराइल ने बृहस्पतिवार को समय की कसौटी पर खरे साबित हुए संबंधों को एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक आगे बढ़ाया और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की। मोदी और नेतन्याहु के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने व्यापार, कृषि, ऊर्जा, साइबरस्पेस और डिजिटल भुगतान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 10 घोषणाएं की गईं। इनमें भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को इजराइल में भी लागू करने का करार भी शामिल है।



यरुशलम में प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहु की मौजूदगी में किए गए समझौतों पर हस्ताक्षर।

उभरती प्रौद्योगिकियों की साझेदारी की भी घोषणा

प्रधानमंत्री मोदी ने एआई, वॉटरम तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में सहयोग को नई गति देने के लिए महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों की साझेदारी की स्थापना की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि इजराइल में यूपीआई के उपयोग के लिए एक समझौता हो गया है। भारत और इजराइल के बीच भारत-पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) के कार्यान्वयन और आई2यू2 (भारत-इजराइल-यूईए-अमेरिका) के ढांचे के तहत सहयोग पर भी चर्चा हुई।

पहले से ही घनिष्ठ रक्षा साझेदारी का विस्तार करने का भी संकल्प लिया। साथ ही भारत और इजराइल ने आपसी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता जताई है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा शांति पहल का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि मानवता

मोदी की झप्पी पूरी दुनिया में अब मशहूर: नेतन्याहु

इजराइली संसद नेसेट में अपने भाषण में नेतन्याहु ने ‘मोदी झप्पी’ शब्द का प्रयोग किया। नेतन्याहु ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत रूप से गले मिलना कुछ खास है और इसे पूरी दुनिया में ‘मोदी झप्पी’ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि जब आप किसी को इतने करीब से गले लगाते हैं तो पता चलता है कि यह वास्तविक है। नेसेट में जोरदार तालियों के बीच नेतन्याहु ने कहा कि वह यह ‘झप्पी’ वापस लौटाना चाहते हैं।

भारत रवाना हुए मोदी

प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा समाप्त करने के बाद बृहस्पतिवार को भारत के लिए रवाना हो गए। इससे मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत-इजराइल साझेदारी आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छूती रहेगी।

को कभी संघर्ष का शिकार नहीं बनना चाहिए। मीडिया बयान में मोदी ने कहा कि भारत का सुरक्षा हित पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता से जुड़ा है।

रणनीतिक साझेदारी का नया इतिहास रचेंगे यूपी-जापान

यामानाशी के गवर्नर का 200 जापानी सीईओ के साथ अग्रस्त में यूपी दौरे का प्रस्ताव

● ग्रीन हाइड्रोजन, उद्योग व तकनीक पर एमओयू को सीएम योगी ने बताया ऐतिहासिक



योगी ने यामानाशी में फेनुक कॉर्पोरेशन का दौरा किया।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : उत्तर प्रदेश और जापान के यामानाशी प्रांत के बीच रणनीतिक साझेदारी की पहल हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के दौरान गुरुवार को यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी ने 200 जापानी सीईओ के साथ अग्रस्त में यूपी का दौरा करने का प्रस्ताव दिया, जिसका योगी ने स्वागत किया। इसे प्रदेश में निवेश, तकनीकी साझेदारी व औद्योगिक विस्तार के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है।

इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और यामानाशी प्रांत के बीच उद्योग, पर्यटन, व्यावसायिक शिक्षा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे भावी क्षेत्रों में सहयोग को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें स्वच्छ ऊर्जा नवाचार, तकनीकी आदान-प्रदान और मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया, आईआईटी कानपुर

उत्तर प्रदेश में निवेश का निमंत्रण

यामानाशी में आयोजित यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो के दौरान गुरुवार को मुख्यमंत्री ने जापानी उद्योग जगत को उत्तर प्रदेश में निवेश का आमंत्रण दिया। कहा, प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थानों के छात्र जापान में प्रशिक्षण लें और सीखी गई तकनीक को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाए।

ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का आधार

मुख्यमंत्री ने यामानाशी स्थित अत्याधुनिक हाइड्रोजन संयंत्र का दौरा किया। उन्होंने पावर-टू-गैस प्रणाली को नजदीक से देखा और विशेषज्ञों से इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मॉडल स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास की दिशा में उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा।

को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह पहल राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएगी।

अनिल अंबानी से ईडी ने की नौ घंटे पूछताछ, सीबीआई ने ठांका नया केस

नई दिल्ली। बैंक धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी बृहस्पतिवार को ईडी के समक्ष पेश हुए। उनसे नौ घंटे पूछताछ के साथ उनका बयान दर्ज किया गया। इस बीच सीबीआई ने अंबानी एवं रिलायंस कन्सल्टिंग (आरकॉम) के खिलाफ 2013-17 के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा से कथित धोखाधड़ी कर बैंक को 2,220 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने के आरोप में नया मामला दर्ज किया है।

ईडी ने पूछताछ के लिए अंबानी को शुक्रवार को भी तलब किया है। यह जांच उनकी कंपनी आरकॉम द्वारा 40,000 करोड़ की बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से संबंधित है। उधर, सीबीआई

● बैंक ऑफ बड़ौदा ने की थी सीबीआई से 2,220 करोड़ की धोखाधड़ी की शिकायत

ने नया मामला दर्ज कर अनिल अंबानी के आवास और रिलायंस कन्सल्टिंग के पंजीकृत कार्यालयों पर छापेमारी कर ऋण लेनदेन से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए। सीबीआई के प्रवक्ता के मुताबिक यह मामला मंगलवार को बैंक से मिली शिकायत पर दर्ज किया गया है।

से जल्द अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता जताई है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा शांति पहल का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि मानवता

अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला 15 चौकियों पर कब्जे का किया दावा

काबुल/इस्लामाबाद, एजेंसी

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने गुरुवार रात डूरेड लाइन के पास पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आक्रामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अफगान रक्षा मंत्रालय और सैन्य अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान की 15 अग्रिम चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के तत्काल सैनिक मारे गए हैं। कई सैनिकों को ज़िंदा पकड़ा गया है।

● पाकिस्तान के हवाई हमलों के जवाब में कार्रवाई, सीमा पर भीषण जंग

तालिबान के प्रवक्ता जहिलुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि यह कार्रवाई पाकिस्तानी सेना की ओर से अफगान क्षेत्र में बार-बार हवाई हमलों के जवाब में की गई है। पूर्वी प्रांतों नंगरहार, कुनार और पक्त्रिया में भारी संघर्ष की खबरें हैं। फस्ट पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मारने और कुछ को बंदी बनाने का भी दावा किया है। अफगान पक्ष ने इस

अभियान में लेजर-गाइडेड सिस्टम से लैस विशेष इकाइयों का उपयोग करने की बात कही है। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने इन हमलों को बिना उकसावे की फायरिंग करार दिया है और कहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में दो घंटे से अधिक समय तक भीषण गोलाबारी जारी रही। यह संघर्ष 22 फरवरी को पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान के नंगरहार और पक्त्रिया प्रांतों में की गई एयरस्ट्राइक के बाद बढ़का है।

हवाई टिकट बुकिंग 48 घंटे में रद्द करने पर पूरा पैसा वापस

नई दिल्ली, एजेंसी

सिंधे एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से बुक किया गया है तो एयरलाइन कंपनियों को उसी व्यक्ति के नाम पर सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना चाहिए। डीजीसीए ने साफ किया है कि ट्रेवल एजेंट या पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने की स्थिति में भी पैसे शर्तों के साथ टिकट करारिया वापसी के नियमों में संशोधन किया है। एयरलाइन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि पैसे वापस करने की प्रक्रिया 14 कार्य दिवसों के भीतर पूरी हो जाए।

डीजीसीए ने यह भी कहा है कि यदि यात्री बुकिंग के 24 घंटों के भीतर नाम में किसी प्रकार की गलती को बताता है और टिकट

सिंधे एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से बुक किया गया है तो एयरलाइन कंपनियों को उसी व्यक्ति के नाम पर सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना चाहिए। डीजीसीए ने साफ किया है कि ट्रेवल एजेंट या पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने की स्थिति में भी पैसे शर्तों के साथ टिकट करारिया वापसी के नियमों में संशोधन किया है। एयरलाइन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि पैसे वापस करने की प्रक्रिया 14 कार्य दिवसों के भीतर पूरी हो जाए।

डीजीसीए ने यह भी कहा है कि यदि यात्री बुकिंग के 24 घंटों के भीतर नाम में किसी प्रकार की गलती को बताता है और टिकट

शासन सख्त मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति देने के लिए 10 मार्च तक अंतिम मौका

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज न करने वाले राज्य के 47,816 कार्मिकों को जनवरी और फरवरी की तनख्वाह मिलेगी। लेकिन एसीपी, यदोन्तित, विजिलेंस क्लीयरेंस, विदेश यात्रा और प्रतिनियुक्ति जैसी सुविधाओं से वंचित रहेंगे। यह आदेश गुरुवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल ने जारी करते हुए वेतन देने में नरमी के साथ नियम सख्त होने संदेश दिया है। उन्होंने बाकी बचे सभी कार्मिकों को 26 फरवरी से 10 मार्च के बीच मानव

इस साल क्या असर पड़ेगा

- ऐसे कर्मचारियों को वर्ष 2026 में एसीपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।
- विदेश यात्रा, प्रतिनियुक्ति और प्रशिक्षण के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस जारी नहीं होगी।
- सेवा अभिलेखों में इसे नियम उल्लंघन के रूप में दर्ज किया जाएगा।
- बड़ी समय सीमा के बाद भी विवरण न देने पर विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई।

में यह भी साफ किया गया है कि 31 जनवरी तक विवरण न देने का प्रभाव पूरे साल संबंधित कर्मचारियों की सेवा में विवरण दर्ज कर पड़ेगा। मुख्य सचिव ने लंबित वेतन जारी किया जाएगा। फरवरी माह के वेतन भुगतान में कोई बाधा नहीं होगी। हालांकि, शासनादेश कर्मचारियों ने अपना संपत्ति विवरण दर्ज नहीं किया है, जिसके चलते उनके विरुद्ध सख्त लेकन चरणबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा है कि जिन कर्मचारियों द्वारा 31 जनवरी तक नियमानुसार संपत्ति विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया था, अब ऐसे सभी कर्मचारियों को 26 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक एक और अवसर दिया गया है। इस अवधि में विवरण दर्ज करने ही जनवरी का लंबित वेतन जारी किया जाएगा। फरवरी माह के वेतन भुगतान में कोई बाधा नहीं होगी। हालांकि, शासनादेश



न्यूज़ ब्रीफ

बिजली इंजीनियर मार्च में करेंगे प्रदेश व्यापी आंदोलन

अमृत विचार, लखनऊ: बिजली को निजी हाथों में देने और बिजली कर्मियों के आवासों में जबरन मीटर लगा कर उथीड़न करने को मुद्दे को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति काफ़ी गुस्से में है। समिति ने तय किया है कि यदि उथीड़न की कार्रवाई नहीं थमी तो विभाग के इंजीनियर और कर्मचारी मार्च और अप्रैल में चरमोच्च तरीके से प्रदेश व्यापी आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि आंदोलन के दौरान क्षेत्रीय एवं परियोजना मुख्यालयों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अप्रैल माह में राजधानी लखनऊ स्थित शक्ति भवन पर विशाल प्रदर्शन होगा। जिन अधिकारियों ने मीटर न लगावाने वाले कर्मचारियों की बिजली काटने के निर्देश दिए हैं, उनके खिलाफ एकआईआर दर्ज कराई जाएगी। समिति ने याद दिलाया कि मार्च 2023 के आंदोलन के उपरांत ऊर्जा मंत्री द्वारा पावर कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर को आंदोलन से संबंधित सभी उथीड़नात्मक कार्रवाइयों को तत्काल वापस लेने के निर्देश दिए गए थे। फिर भी उथीड़न की प्रक्रिया जारी है। संघर्ष समिति के मुताबिक निजीकरण के विरोध में पिछले 15 महीनों से जारी आंदोलन के दौरान अल्प वेतनभोगी सद्विदा कर्मियों को सेवा से हटाया गया है। बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। साथ ही फ़ैसलबल अटेंडेंस के नाम पर वेतन रोके जाने जैसी कार्रवाइयों से कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है।

सीधे जनता से हो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव

अमृत विचार, लखनऊ: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बलेट पेपर से कराने के साथ इसबार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव सीधे जनता से कराने की मांग उठाई। उनका कहना है कि मतदान बलेट पेपर से होने पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बन सके। उन्होंने यूथीसी के मुद्दे पर भाजपा पर तीखा हमला बोलेते हुए कहा कि 'बंटो और राज करो' की राजनीति कर रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुरुवार को सांसद संजय सिंह ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में जनता की सीधी भागीदारी नहीं है, जिससे जनानदेश कमजोर होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता के दुरुपयोग के जरिए जिला पंचायत चुनावों को प्रभावित करती है। अगर सरकार वास्तव में लोकतंत्र में विश्वास रखती है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से कराए और बलेट से मतदान सुनिश्चित करे।

अफसरों की गोपनीय रिपोर्ट होगी डेटा आधारित

अमृत विचार, लखनऊ: शासन ने अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए इसे पूरी तरह डेटा आधारित बनाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने गुरुवार को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अब केवल सामान्य टिप्पणी नहीं, बल्कि लिखित मामलों, नए वादों और निरस्तारित प्रकरणों की संख्या (डेटा) को एसीआर का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाएगा। शासननिदेश के अनुसार यह व्यवस्था भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा/पीसीएस) के सभी अधिकारियों पर लागू होगी। अधिकारियों को अब स्वरो पोर्टल पर अपनी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के लिए स्व-मूल्यांकन करते समय यह डेटा अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा है कि रिपोर्टिंग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, स्वीकृति अधिकारी तीनों को अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए लिबंटि, नए और निरस्तारित मामलों के डेटा को खान में लेते हुए ही अपना मूल्यांकन करना होगा।

सिंगापुर से जापान तक ‘महाराज’ का डंका

अमृतपूर्व सफलता से भरा रहा योगी का दौरा, 1.5 लाख करोड़ के एमओयू, 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान का चार दिवसीय विदेश दौरा निवेश, तकनीक और वैश्विक साझेदारी के लिहाज से अभूतपूर्व रूप से सफल रहा। इस दौरान हुए उच्चस्तरीय निवेश संवादों में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1.5 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जबकि 2.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। यह दौरा वर्ष 2029–30 तक उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

जापान दौरे के दौरान कृषि मशीनरी, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग जैसे भविष्य के क्षेत्रों में बड़े निवेश प्रस्ताव सामने आए। जापान में जिन प्रमुख कंपनियों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित हुए, उनमें कुबोटा कॉर्पोरेशन, स्पार्क मिंडा (टोयो डेन्सो के सहयोग से), जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स के इंडस्ट्री और नागासे एंड कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बी 2जी (सरकार से सरकार) बैठकों में सुजुकी मोटर

‘जापान सिटी’ और ऑटो क्लस्टर की योजना

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वीडा) क्षेत्र में 500 एकड़ में ‘जापान सिटी’ विकसित की जाएगी, जहां जापानी कंपनियों के लिए विशेष औद्योगिक वातावरण तैयार होगा। इसके साथ ही ऑटो आईएम और कंपोनेंट निर्माताओं के लिए डेडिकेटेड ऑटो क्लस्टर और आरएंडडी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ‘इन्वेस्ट यूपी’ में जापान डेस्क को और मजबूत किया जाएगा, जिसकी निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने एल-जीरो सीरीज मैग्लेव ट्रेन की यात्रा और फानुकु कॉर्पोरेशन के रोबोटिक्स व फैक्ट्री ऑटोमेशन संयंत्र का भी दौरा किया। फानुकु ने उत्तर प्रदेश में निवेश और एमएसएमई सेक्टर के तकनीकी उन्नयन में सहयोग की इच्छा जताई।

सिंगापुर में भी मिला निवेशकों का भरसा

सिंगापुर में आयोजित इन्वेस्टर रोड शो के दौरान एमआरओ, कार्गो हब, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, रिकलिंग और फिनटेक क्षेत्रों में व्यापक सहयोग पर सहमति बनी। विशेष रूप से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को एमआरओ और कार्गो हब के रूप में विकसित करने पर सहयोग चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के इस दौरे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुका है। 1.5 लाख करोड़ के एमओयू और 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव इस बात का प्रमाण हैं कि प्रदेश का वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का लक्ष्य अब दोस धरातल पर आगे बढ़ रहा है।

कॉरपोरेशन, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड, कोनोइके ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड, पैपिडस कॉरपोरेशन, मारुबेनी कॉरपोरेशन, सुमितोमो रिचिलिटी एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और एमयूएफजी बैंक जैसी दिग्गज कंपनियों ने सहभागिता की। इन कंपनियों ने उत्तर प्रदेश को एशिया का उभरता हुआ निवेश केंद्र बताते हुए राज्य में दीर्घकालिक निवेश में रुचि जताई। जापान दौरे की एक बड़ी



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान दौरे के दौरान गुरुवार को यामानाशी प्रांत में दुनिया की अत्याधुनिक सुपरकंडक्टिंग मैग्लेव हार्ड-स्पीड ट्रेन की सवारी की, जो परीक्षण के दौरान 500 किलोमीटर प्रतिघंटा तक की रफ्तार हासिल करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी तेज गति के बावजूद ट्रेन बेहद स्थिर, सुरक्षित और आरामदायक रही।

निवेश प्रस्तावों से 5 लाख से अधिक रोजगार की उम्मीद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चार दिवसीय सिंगापुर और जापान दौरा रोजगार, निवेश और तकनीकी साझेदारी के लिहाज से ऐतिहासिक साबित हुआ है। इस विदेश यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार को कुल 1.5 लाख करोड़ के एमओयू और लगभग 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से प्रदेश में 5 लाख से अधिक युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि जापान में 90 हजार करोड़ के एमओयू और करीब 1.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, जबकि सिंगापुर में 60 हजार करोड़ के एमओयू और लगभग 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सभी समझौतों और प्रस्तावों को इन्वेस्ट यूपी और अन्य संबंधित विभाग समयबद्ध ढंग से लागू करेंगे, ताकि रोजगार सृजन का लाभ शीघ्र जमीन पर दिख सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा केवल समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि टेकनोलॉजी ट्रांसफर, रिकलिंग और औद्योगिक निवेश के जरिए प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का माध्यम बनेगी। जापान और सिंगापुर दोनों देशों ने युवाओं के प्रशिक्षण, कौशल विकास और एमएसएमई सेक्टर में तकनीकी सहयोग के लिए सकारात्मक रुख दिखाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यामानाशी के गर्भर अगस्त माह में लगभग 200 जापानी सीईओ के साथ उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, जिससे निवेश प्रस्तावों को अंतिम रूप मिलेगा और रोजगार सृजन की प्रक्रिया तेज होगी।

11 करोड़ नकद, जेवर, महंगी घड़ियां और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले

बसपा विधायक पर एक हजार करोड़ की टैक्स चोरी करने की आशंका

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: बलिया के रसड़ा से बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह और उनके नजदीकियों कि ठिकानों पर दूसरे दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी रही। सूत्रों का दावा है कि अभी तक 11 करोड़ से अधिक नकद बरामद हुए हैं, वहीं काफ़ी मात्रा में जेवर, महंगी घड़ियों के साथ ही लेनदेन और करोड़ों की बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। विधायक द्वारा किए कारोबार में करीब एक हजार करोड़ रुपए के टैक्स चोरी की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि आयकर विभाग की ओर से अधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। छापेमारी के दौरान पुलिस का कड़ा पहरा रहा। आयकर विभाग की टीम ने बुधवार को बसपा विधायक

भाजपा के छापे सरकारी डकैती होते हैं

बसपा प्रमुख मायावती और योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बाद अब अखिलेश यादव भी बसपा विधायक के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा के छोले लोगों के कमाए गए पैसों को लूटने के काम करते हैं। भाजपाई जहां भी देखते हैं कि कहीं धन-दौलत जमा होने की संभावना है, वहीं एजेंसियां लेकर पहुंच जाते हैं। भाजपाई हृदयहीन हैं, इसलिए संवेदनहीन भी हैं।



उमाशंकर सिंह के लखनऊ के विपुलखंड स्थित आवास के साथ ही बसपा विधायक के ठिकानों के साथ ही मिजापुर और प्रयागराज में सहयोगियों के कई ठिकानों पर छापा मारा था। यह कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। बुधवार की रात करीब 11 बजे विधायक के लखनऊ स्थित आवास के लोके कार्रवाई समाप्त कर दी गई, लेकिन विपुलखंड में ही स्थित छात्र शक्ति केंद्रस्थान कंपनी के कारपोरेट आफिस में पहुंच कर टीम ने जांच शुरू कर दी। बलिया स्थित विधायक के गांव खनवर स्थित आवास के साथ ही रसड़ा स्थित होटल स्काई के अलावा विधायक के खास लोगों में शुमार भूपेन्द्र सिंह और प्रवीण सिंह के यहां पर छापेमारी की गई। सोनभद्र में साईराम इंटर प्राइजेज के साथ ही ठेकेदार के फैंजी के ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी रही। इसके अलावा सोनभद्र में अन्य खनन कारोबारी जो कि किसी न किसी रूप में विधायक से जुड़े रहे उन सभी के यहां पर भी छापेमारी जारी रही।

डायरी खोलेगी सत्ता और सियासत की सांठगांठ का सच

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के यहां छापे में नकदी, जेवर के साथ ही कथित तौर पर एक डायरी भी मिली है। डायरी में जहां शासन और प्रशासन के कई बड़े अफसरों को लेन-देन का ब्यौरा है, वहीं कई नौकरशाहों की ब्लैक मनी भी खनन और ठेकों में एडजस्ट करने के दस्तावेज भी मिले हैं। साफ है कि डायरी में एक तरह से सत्ता और सियासत की सांठगांठ का सच दर्ज है। उधर डायरी मिलने की खबर फैलने के साथ ही कई अफसरों और सफेदपोशों की बचैनी बढ़ती जा रही है। विधायक उमाशंकर सिंह ने जब से सियासत में कदम रखा, तब से उनके रसूख के साथ ही संपत्ति भी अमरबल की तरह बढ़ती रही। विधायक बने के बाद तो संपत्तियों में काफ़ी इजाफा होता रहा। उनके रसूख का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भले

ही वह बसपा से तीन बार के विधायक हैं, लेकिन सत्ता चाहे सपा की रही हो या फिर भाजपा की। उनसे संबंधित कंपनियों को सड़क निर्माण के साथ ही खनन के ठेके भी मिलते रहे हैं। यहां तक कि नियमों को ताक पर रखकर भी ठेके दिए जाते रहे। सपा सरकार में जहां वह एक कद्दावर मंत्री के ठेकों में पार्टनर रहे, वहीं अगस्त 2025 में उमाशंकर सिंह से जुड़ा पत्थर खनन का मामला सामने आया था। उमाशंकर की पत्नी की कंपनी छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन ने सोनभद्र में खनन का पट्टा लिया था। कंपनी ने 3,000 रुपए प्रति घनमीटर के रेट से पत्थर खनन का का पट्टा लिया था, जबकि रायल्टी दर 160 रुपए प्रति घनमीटर थी। आरोप लगा था उमाशंकर की पत्नी की कंपनी

विधायक के बेटे ने कहा: हम पूरा सहयोग कर रहे हैं

विधायक उमाशंकर सिंह के बेटे प्रिंस युकेश सिंह ने गुरुवार को चुप्पी तौड़ी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि कल गोमतीनगर आवास पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से जांच की गई। उनके पिता, वह स्वयं और परिवार के अन्य सदस्य विभाग के अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। इनकम टैक्स अधिकारी भी पूरी प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं।

आईटीबी बर्लिन में दिखेगी यूपी पर्यटन की सशक्त मौजूदगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: विश्व पर्यटन उद्योग के सबसे प्रतिष्ठित मंच आईटीबी बर्लिन में उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध पर्यटन सफ़्ट और आधुनिक पर्यटन संभावनाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 3 से 5 मार्च तक आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय आयोजन में उत्तर प्रदेश पर्यटन वैश्विक पर्यटन विशेषज्ञों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं से सीधा संवाद करेगा।

बदलती प्राथमिकताओं के अनुसार प्रदर्शनी

आईटीबी बर्लिन-2026 में प्रदर्शनी को पारंपरिक पर्यटन तक सीमित न रखकर एडवेंचर टूरिज्म, बिजनेस ट्रेवल, एलजीबीटीक्यू ट्रेवल, लजरी ट्रेवल, मेडिकल टूरिज्म और ट्रेवल टेकनोलॉजी जैसे विविध सेगमेंट्स में विभाजित किया गया है। इसका उद्देश्य बदलती वैश्विक प्राथमिकताओं और यात्रियों की नई अपेक्षाओं को मंच प्रदान करना है। जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पर्यटन का भव्य पर्वेलियन इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगा। पर्वेलियन में अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में साइनेज, रचनात्मक डिस्प्ले, वीडोआईपी लाउंड्रज, हस्तशिल्प कलाकृतियां और ओडीओपी को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटन विभाग की वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशन, पर्यटन सफ़्ट, वेलेनेस और मेडिकल टूरिज्म की भी व्यापक प्रस्तुति की जाएगी।

सम्मान देने के साथ-साथ आने वाले वर्षों की रूपरेखा तय करने का भी संदेश देती है।

छापे के पीछे कौन

अमृत विचार: विधायक के साथ ही मैनेजमेंट में माहिर माने जाने वाले उमाशंकर सिंह के यहां छापे पड़ा है तो तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसमें अहम सवाल यह है कि आखिरकार बसपा बसपा विधायक के यहां आयकर के छापे के पीछे कौन है? ऐसी कौन सी बड़ी शक्ति है, जिसके इशारे पर बसपा प्रमुख मायावती के खास खास रहे विधायक के यहां कार्रवाई हुई। वह भी जब विपक्ष बसपा को कथित तौर पर भाजपा की बी टीम बताता रहा है। हालांकि सरसरी तौर पर पत्थर खनन में कैंग की रिपोर्ट और विजीलेंस की जांच को ही छापे के पीछे असल वजह माना जा रहा है, लेकिन लोगों के गले से यह बात नहीं उतर पा रही है।

50 हजार का इनामी गो-तस्कर वाराणसी से गिरफ्तार

अमृत विचार, लखनऊ: एसटीएफ ने 50 हजार के इनामी गो-तस्कर को वाराणसी के लोहा से गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ चंदौली में दो वर्ष पूर्व एकआईआर दर्ज की गई थी। तभी से फरार चल रहा था। आरोपी पर पुलिस ने इनाम घोषित किया था। एसटीएफ के मुताबिक बुधवार देर रात को विशेष ऑपरेशन के दौरान आरोपी मो. अशरद को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ के डिप्टी एसपी शैलेश प्रताप सिंह के मुताबिक पकड़ा गया गो-तस्कर मो. अशरद वाराणसी स्थित सिगरा के लहंगपुरा का रहने वाला है। उसके खिलाफ चंदौली में दो वर्ष पूर्व गो-तस्कर की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बुधवार देर रात को सूचना मिली कि मो. लोहात के धर्मिरायें मैदान के पास है। वह भागने की तैयारी कर रहा है। टीम ने घेरावदी कर रात 10 बजे दबोच लिया। वह क्षेत्र में लोगों को धमकाने व मारपीट करने के मामलों में आरोपी है।

सांझी रेखा

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के समूह ने आटा और मंदिरों के चढ़े फूलों ने तैयार किया हर्बल गुलाल

अयोध्या व काशी में मक्का के गुलाल से खेली जाएगी होली

प्रशांत सक्सेना, लखनऊ

● खराब नहीं होगी त्वचा, आंख व मुंह में जाने पर नहीं होगा नुकसान

गुलाल की कीमत (रुपया प्रति किलो)

- गुलाल-थोक - 350-400
- गुलाल-फुटकर - 500
- गुलाल-200 ग्राम - 100



चिनहट के उत्तरधौना में सुखाया जाता गुलाल और टोकरियों में रखा तैयार गुलाल।

एक तरफ महिलाओं ने स्वास्थ्य को देखते हुए हर्बल गुलाल बनाया है तो दूसरी तरफ इस कार्य से उन्हें रोजगार मिला है। लोग इस हैम्पेड सामग्री को खरीद कर उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं।

-अजीत कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, लखनऊ

मंदिरों से एकत्र किए फूल महिलाएं लाई सज्जियां

समूह की अध्यक्ष वंदना सिंह ने बताया कि इस कार्य में 18 समूह की महिलाएं जुड़ी हैं। मक्का किसानों से खरीदकर आटा बनाया है, जबकि फूल मंदिरों के चढ़े हुए एकत्र किए हैं। महिलाएं खेती-बाड़ी से जुड़ी हैं, इनके द्वारा धनिया, पालक, चुकंदर एकत्र किया गया है। कोषाध्यक्ष सोनी सिंह बताती हैं कि 40 पीसद तक बचत होती है। एक स्टॉल में चार से पांच हजार की बिक्री हो रही है।

सात विंटरल तक भेजी गुलाल की खेप

20 विंटरल उत्पादन कक्ष से साप्ते 15 विंटरल तक गुलाल तैयार किया है। इसमें अयोध्या, वाराणसी के खासकर काशी और मिर्जापुर में सात विंटरल गुलाल बिक चुका है और भी मांग आई है। इसके अलावा अंबेडकर नगर, बरौती, सोनभद्र, लखीमपुर, हरदोई व कानपुर से मांग आने पर खेप भेजी जा रही है। लखनऊ में भी महिलाएं स्वयं थोक व फुटकर स्टॉल लगाकर बिक्री कर रही हैं। 128 फरवरी से विकास भवन, कलेक्ट्रेट, विश्वविद्यालय समेत अन्य सरकारी परिसरों में स्टॉल लगाए जाएंगे।

होली में खपाने के लिए जा रही शराब बरामद, तीन गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: होली में खपाने के लिए बिहार शराब ले जा रहे तीन तस्करों को एसटीएफ ने बलिया के बैरिया दबोच लिया। उनके पास से 471 पेट्टी शराब, बिस्तर, पिकअप, तीन मोबाइल व नकदी बरामद की गई है। यूपी से बिहार भेजने के लिए तस्करों ने गंगा नदी के रास्ते का प्रयोग किया। एसटीएफ के डिप्टीएसपी अचनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक यूपी से बिहार शराब तस्करी की सूचनाएं मिल रही थी। होली में बड़े पैमाने पर तस्करी का इनपुट मिला था। विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने गुरुवार सुबह 4.30 बजे बलिया के बैरिया स्थित

नाव से गंगा पार ले जाते थे शराब

एसटीएफ के डिप्टी एसपी अचनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक आरोपियों ने फूलाछ में बताया कि उनका गिराह गंगा नदी के रास्ते शराब की तस्करी करता है। शराब बलिया के बैरिया इलाके में पहुंचने के बाद नाव से गंगा नदी पार करार बिहार पहुंचाते थे। पुलिस के अनुसार बैरिया क्षेत्र के चिरियामोड़ स्थित एक लाइसेंस गैदास से शराब अवैध रूप से उपलब्ध कराई जाती थी, जिसे गिराह के सदस्य बिहार पहुंचाते थे। तीनों आरोपियों के खिलाफ बैरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज किया गया है। वहीं आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से जेल भेज दिया गया है।

पूर्वी भवन टोला गंगा किनारे बंधे पास से दो पिकअप वाहन रोककर तलाशी ले। इस दौरान अंदर भारी मात्रा में शराब व बिस्तर की पेटियां मिलीं। एसटीएफ ने मौके से बलिया के बांसडीह स्थित हुसैनाबाद निवासी धर्मजीत भारती, कोतवाली नगर बहादुरपुरा का पिंटू प्रसाद और बैरिया निरैया मोड़ निवासी करन बहादुर साह उर्फ घुरघुर को गिरफ्तार किया।



पिंटू प्रसाद, करन कुमार साह, धर्मजीत भारती

मिलते-जुलते नामों, डिजाइन व कलर स्कीम से प्रभित न हों केवल असली होलोग्राम युक्त एम. के. बन्धानी हींग ही खरीदें पाँच पीढ़ी की विश्वस्तरीय हींग परम्परा पुण्यलोक गोलेकवासी बाबू किशोर चन्द कपूर 'किशोर जी' के आशीर्वाद से अभिसिंचित एवम् संचालित

एम.के. बन्धानी हींग
श्री के.एन. डिस्ट्रीब्यूटर



रिक्त केन्द्र : नारायण प्लाजा, 51/71 नवागंज कानपुर 208001, फोन - 9519456555 9695416555

न्यूज ब्रीफ

मंडलस्तरीय पशु आरोग्य मेला 28 को

अमृत विचार, लखनऊ: मोहनलालगंज की ग्राम पंचायत भौदरी के मजरा गनियार में 28 फरवरी को मंडलस्तरीय वृहद पशुआरोग्य मेला आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उद्घाटन करेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेश कुमार ने बताया कि मंडल स्तरीय मेले में लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई के पशुओं की गंभीर बीमारी का उपचार, टीकाकरण, जांच, आदि की जाएगी। इसके अलावा पशुओं की सर्जनी भी की जाएगी। इसके लिए विशेष सर्जन और चिकित्सकों की टीम बनाई है। पशुपालकों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा बल्कि दवाएं भी निशुल्क दी जाएंगी। अन्य जिलों के पशुपालकों भी मेले का लाभ उठा सकते हैं। विभाग ने कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी है।

फर्जी साइबर शिकायत से ठप हुआ कारोबार

अमृत विचार, लखनऊ: सेक्टर-6ए निवासी शैरी सिंह उर्फ स्नेहा ने बताया कि वह वर्ष 2017 से ऑनलाइन हैडक्राफ्ट स्टोर चला रही है। उनके हैडक्राफ्ट की मांग देशभर में है। महाराष्ट्र निवासी नगमा नामक महिला ने उनसे कपड़े ऑर्डर कर उनसे अतिरिक्त रंग करारों को कहा था। स्नेहा ने रंगार्थ में अतिरिक्त समय लगने की बात पहले ही दे दी थी। इसपर नगमा ने उन्हें बदनाम करना शुरू कर दिया। आरोप है कि नगमा ने सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक रिपोर्ट अपलोड कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। आरोप है कि नगमा ने महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत कर उनका एचडीएफसी बैंक खाता फ्रीज करवा दिया।

परिवहन निगम में वे-बिल घोटाले का खुलासा, जांच शुरू

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: परिवहन निगम में वे-बिल के जरिए भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आलमबाग डिपो में कार्यरत परिचालक अमित ठाकुर ने वर्ष 2019 में जारी वे-बिल का उपयोग जनवरी 2026 में किया। साथ वर्ष 2019 में वे-बिल को रजिस्टर और कंप्यूटर में दर्ज किए बिना इस्तेमाल करने का आरोप है। इस गड़बड़ी से परिवहन निगम को करीब 40 हजार रुपये का नुकसान हुआ है।

सूत्रों के मुताबिक वे-बिल जब किसी परिचालक को आवंटित किया जाता है तो उसे रजिस्टर में चढ़ाया

रेरा का 35वां रियल एस्टेट एजेंट प्रशिक्षण सत्र शुरू

अमृत विचार, लखनऊ: रियल एस्टेट को अधिक पारदर्शी एवं उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए उग्र भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गुरुवार को कानपुर रोड स्थित इंडियन लिटरेसी बोर्ड में चार दिवसीय 35वां रियल एस्टेट एजेंट प्रशिक्षण सत्र शुरू किया गया। उद्घाटन अध्यक्ष संजय भूस्वरेड्डी ने किया। प्रदेशभर के 53 एजेंटों ने प्रतिभाग किया।

मेट्रो स्टेशन के नीचे किशोरी से छेड़छाड़, भागी तो शोहदे ने निकाला चाकू

संवाददाता, आलमबाग

अमृत विचार: आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे बड़ी बहन संग गयी किशोरी से मोहल्ले में रहने वाले युवक ने छेड़छाड़ की। पीड़िता बचने के लिए भागी तो आरोपी ने पीछा किया और मेट्रो स्टेशन परिसर में चाकू निकालकर दोनों बहनों और सहेली पर टूट पड़ा। सुरक्षाकर्मियों को आता देख आरोपी धमकाते हुए भाग निकला। आलमबाग पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आलमबाग निवासी पिता ने बताया कि

- किशोरी, उसकी बड़ी बहन व सहेली पर टूट पड़ा आरोपी, सुरक्षाकर्मियों को देख भागा
- पिता की तहरीर पर आलमबाग कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज, आरोपी गिरफ्तार



कुलदीप कश्यप

बुधवार सुबह करीब 9:40 बजे उनकी बड़ी बेटी छोटी बहन को लेकर सहेली को किताब देने आलमबाग मेट्रो स्टेशन गयी थी। बड़ी बेटी सहेली को किताब देने ऊपर चली गयी। इस दौरान छोटी बहन नीचे खड़ी थी। इसी दौरान मोहल्ले

में रहने वाला कुलदीप कश्यप उर्फ बडवा दोनों बहनों का पीछा करते हुए मेट्रो स्टेशन के नीचे पहुंच गया। आरोपी छोटी बेटी के पास खड़े होकर अश्लील इशारे करने लगा। कुलदीप पीछा करते हुए उसे पकड़ने का प्रयास करते हुए ऊपर पहुंच गया। पीड़िता अपनी बड़ी बहन और उसकी सहेली के पास पहुंच गयी। यद्द देख आरोपी ने चाकू निकाल लिया।

चाकू मारने की बात कहते हुए उनसे भिड़ गया। इसी दौरान मेट्रो सिन्क्योरिटी को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। पीड़िता ने पिता को कॉल कर सूचना दी तो वे मौके पर पहुंचे। बेटियों से बात करने के बाद पिता ने आलमबाग पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पिता की तहरीर पर छेड़छाड़, धमकी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने आरोपी कुलदीप उर्फ बडवा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को जेल भेज दिया है।

2022 में लखनऊ आरटीओ ने दो बार सीज की थी बस

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हादसा: फिटनेस चुस्त, मगर बॉडी में किया बदलाव

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: गोसाईगंज के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना हुई बस की शुरुआती जांच में तीन प्रमुख कमियां उजागर हुई हैं। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि बस की भौतिक संरचना में मानकों के विरुद्ध बदलाव कर उसे बढ़ाया गया था, जबकि कागजी फिटनेस और बीमा वैध पाए गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नियमों के विपरीत संशोधित बस को फिटनेस प्रमाणपत्र कैसे मिला।

400 स्लीपर बसें गुजरती हैं, चेकिंग बनी चुनौती

आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय के अनुसार लखनऊ से होकर प्रतिदिन लगभग 385 से 400 स्लीपर बसें गुजरती हैं। अवैध बस घाइट से रोजाना आठ से दस हजार यात्री सफर करते हैं। ये बसें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और बिहार के बीच संचालित होती हैं। शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ के आरटीओ व एआरटीओ प्रवर्तन अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। जांच में चेकिंग दलों और ट्रांसपोर्टों की संभावित मिलीभगत की भी पड़ताल की जा रही है।



जिससे कि ज्यादा सीट बनायी जा सके। बैठने के लिए 32 सीटों के बजाय केवल नौ सीटें थीं। यानी क्षमता से दोगुनी सवारियां बैठाई जा रही थीं, जिससे वाहन की अनियंत्रित होने की आशंका बढ़ गई। इम्पर्जेंसी गेट बंद मिले और परमिट की शर्तों का भी उल्लंघन पाया गया। 2022 में दो बार व 2023 में बस को उल्लंघन की वजह से बंद किया गया था

दो घंटे का विशेष अभियान, 326 के खिलाफ कार्रवाई

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हंगामा करने वालों के खिलाफ कमिश्नरेंट पुलिस ने बुधवार से विशेष अभियान शुरू कर दिया है। रात 9 से 11 बजे तक चलने वाले विशेष अभियान में बुधवार को पहले दिन 329 स्थान पर चेकिंग की गई। इस दौरान 2211 लोगों का परीक्षण किया गया। 326 लोग शराब के नशे में मिले। उनके खिलाफ विविध कार्रवाई की गई।

- सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान
- कमिश्नरेंट के 329 स्थान पर 2211 लोगों की हुई चेकिंग

पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेगर के मुताबिक अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेगर के निर्देश पर जेसीपी एलओ बबलू कुमार ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। बुधवार

लाल चंदन की खेती में निवेश के नाम पर ठगे 9.28 करोड़

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: आंध्र प्रदेश में लाल चंदन की खेती का सरकारी टेंडर मिलने का झांसा देकर जालसाजों ने कारोबारी से 9.28 करोड़ रुपये ऋण लिए। आश्वासन दिया कि खेती पर दस साल बाद 700 करोड़ का मुनाफा होगा। रुपये देने के बाद पीड़ित आंध्र प्रदेश गए तो वहां कोई खेती नहीं मिली। कोर्ट के आदेश पर गोमतीनगर पुलिस ने गुरुवार को चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। साउथ सिटी निवासी हेमंत कुमार राय गोमतीनगर के विवेकखंड स्थित श्रेया इंफ्रा एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। उन्होंने

गर्हा। कार्रवाई करने में पश्चिमी जोन सबसे आगे रहा। पश्चिम जोन में 116 स्थानों पर 846 लोगों की जांच कराई गई। जिसमें 204 का चालान काटा गया। मध्य जोन में 79 स्थान पर 453 लोगों की चेकिंग 28 का चालान, पूर्वी जोन में 58 स्थान पर 378 की जांच कर 33 लोगों का चालान काटा गया। इसी तरह दक्षिणी जोन में 46 स्थानों 259 लोगों को चेक कर 25 का और उत्तरी जोन में 30 स्थानों पर 275 लोगों की जांच कर 36 का चालान काटा गया।

आंध्र प्रदेश में बताया था सरकारी टेंडर, गोमतीनगर थाने में रिपोर्ट

बताया कि कंपनी में आंध्र प्रदेश के कुरनूल निवासी जे. पुलैया, नागोरेड्डी, पी. लक्ष्मी नारायणा और पी. महेश्वर का आना-जाना था। दिसंबर 2022 में बातचीत में चारों ने बताया उन्हें बताया कि आंध्र प्रदेश के प्रकाशम और नादय्याल जिले में लाल चंदन की खेती होती है। उन्हें इसका सरकारी टेंडर मिला है। लाल चंदन के पेड़ लगाने के लिए करीब छह करोड़ की 100 एकर की जमीन लेनी है। आरोपियों ने निवेश के 10 साल बाद 700 करोड़ का मुनाफा देने की बात कही।

अधिशासी अभियंता विद्युत और यूपीसीडा को चार्जशीट के निर्देश

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: औद्योगिक क्षेत्र अमौसी/नादरगंज में अवस्थापना सुविधाओं की समीक्षा में जिलाधिकारी विशाख जी को नाला, कलवट व मीडियन निर्माण की प्रगति धीमी मिली। इसके अलावा विद्युत विभाग द्वारा स्वीकृत बजट के सापेक्ष व्यय एवं प्रगति भी संतोषजनक नहीं पाई। नाराजगी जताते हुए अधिशासी अभियंता यूपीसीडा और अधिशासी अभियंता विद्युत के खिलाफ चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए।



कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय उद्योग बंधु के साथ बैठक लेते जिलाधिकारी विशाख जी।

- उद्योग बंधु की बैठक में खराब प्रगति पर जिलाधिकारी विशाख जी ने जताई नाराजगी
- यूपीसीडा को 31 मार्च तक सभी निर्माण पूर्ण करने की चेतावनी

जिलाधिकारी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु की महत्वपूर्ण बैठक की। संबोधित अधिकारियों के साथ विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की विभागावार समीक्षा की। इस दौरान अधिशासी अभियंता यूपीसीडा ने अवगत कराया कि औद्योगिक क्षेत्र

स्मार्ट मीटर और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई से नाराजगी

अमृत विचार, लखनऊ: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों और जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में आंदोलन हेज करने की चेतावनी दी है। समिति ने गुरुवार को आयोजित बैठक में निर्णय लिया कि यदि विभागीय स्तर पर कार्रवाई नहीं रोकी गई तो मार्च और अप्रैल में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू किया जाएगा। समिति ने बताया कि कोरपोरेशन के चेयरमैन को जल्द ही ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की समस्याओं और विरोध से अवगत कराया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि मार्च में क्षेत्रीय और परियोजना मुख्यालयों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।

उर्जा मंत्री से मिला जूनियर इंजीनियर्स संगठन

अमृत विचार, लखनऊ: राउच विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को केंद्रीय अध्यक्ष गोपाल वल्लभ पटेल के देखरेख में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से मुलाकात की। इसमें वर्ष-23 में लेसा की सांकेतिक हड़ताल के खत्म होने पर बनी सहमति के अनुरूप कर्मचारियों पर की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्रवाई समाप्त करने की मांग दोहराई। अमौसी जोन में जूनियर इंजीनियरों और प्रोन्नत अभियंताओं के खिलाफ किए गए सामूहिक निलंबन और संबद्धीकरण के आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग भी की। महासचिव बलवीर यादव ने संसाधनों की कमी, लंबी दूरी के निरीक्षण और अतिरिक्त दायित्वों को समस्या की जड़ बताया। प्रतिनिधिमंडल ने निष्पक्ष जांच और एकतर्फी कार्रवाई समाप्त करने की मांग करते हुए प्रबंधकीय जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया।



जूनियर इंजीनियर्स के प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा मंत्री से की मुलाकात।



कार्यक्रम में बोलते डॉ. नीरज सिंह।

नए मतदाताओं के पंजीकरण को दें प्राथमिकता: नीरज सिंह

अमृत विचार, लखनऊ: भाजपा नेता डॉ. नीरज सिंह ने एसआईआर अभियान के अंतर्गत आज लखनऊ पूर्वी विधानसभा के शंकर पुरवा वार्ड तृतीय स्थित बूथ संख्या-236 पर बूथ प्रयास किया। पंतनगर सांस्कृतिक समिति, रामलीला मैदान, पंतनगर खुर्दम नगर में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए बूथ स्तर पर चल रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की तथा नए मतदाताओं के पंजीकरण कार्य को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। डॉ. नीरज सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा करते हुए बूथ को और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने पर बल दिया। प्रवीण गार्ग ने बताया कि कार्यक्रम में बूथ अध्यक्ष अनिल कश्यप, नरेंद्र सिंह देवडी, उमेश चंद्र उपस्थित रहे।

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में क्वांटम प्रौद्योगिकी पर संगोष्ठी

अमृत विचार, लखनऊ: इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) उत्तर प्रदेश की ओर से गुरुवार को इंजीनियर्स भवन रीवर बैंक कॉलोनी में क्वांटम प्रौद्योगिकी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने क्वांटम प्रौद्योगिकी ने सेमीकंडक्टर, लेजर, एमआरआई, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष यात्रा जैसे आविष्कारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी है। मुख्य अतिथि प्रो. ओंकार प्रसाद अध्यक्ष भौतिकी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्यूबिट, अध्यारोपण सिद्धांत और क्वांटम कलन-विधियों को सरल शब्दों में समझाया।



नवयुग कन्या में आयोजित कार्यक्रम में विचार रखती वक्ता।

बुद्ध पार्क की धीमी प्रगति पर ठेकेदार को नोटिस, निरस्त हो सकता अनुबंध

उपाध्यक्ष ने कानपुर रोड योजना स्थित गौतम बुद्ध पार्क-1 का भी निरीक्षण किया। पार्क में ले-आउट के मुताबिक कार्य की प्रगति संतोषजनक न मिलने पर नाराजगी जताई। कार्यदायी संस्था मेसर्स एफईएजी इंजीनियर्स एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदार को हिदायत दी कि यदि एक माह में कार्य में सुधार नहीं हुआ तो अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।

अवसर पर लोगों के लिए यह थीम पार्क खोल दिया जाएगा। अधीक्षण अभियंता नवनीत शर्मा ने बताया कि आशियाना के सेक्टर-के में स्थित वनस्थली पार्क थीम आधारित है। ये पीपीपी मोड पर लगभग 12 करोड़ की लागत से मैजिकल लैंड फैटसी पार्क विकसित किया जा रहा है। पार्क में निष्प्रेयोय्य सामग्री के इस्तेमाल से मरमेड, फीनिक्स,



आशियाना का वनस्थली पार्क का निरीक्षण करते उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार।

ज्योतिबा फुले जोनल पार्क में शुरू होंगे चार फाउंटेन

उपाध्यक्ष ने ज्योतिबा फुले जोनल पार्क का भी निरीक्षण किया। पार्क में लगभग चार करोड़ से विकास एवं सर्वोद्योग के कार्य करवा जा रहे हैं। पार्क में नये सिरे से विकसित करके वॉटर बॉडीज में डांसिंग फाउंटेन, बॉल फाउंटेन, रिंग फाउंटेन व पीकोक फाउंटेन स्थापित किये जाएंगे। इसके अलावा जॉइंगिंग ट्रैक के पास 25 साउंड स्पीकर व थीमेटिक लाइटिंग की जाएगी। इसे भी अप्रैल 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।



न्यूज़ ब्रीफ

फर्जीवाड़ा कर जमीन बेचने वाला गिरफ्तार

अमृत विचार, मलिहाबाद: जाली दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने वाले आरोपी को मलिहाबाद पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। इस्केटर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी आठ गद्दी सौदा निवासी अहमद अली है। 14 नवंबर 2025 को गोमतीनगर विस्तार निवासी अभिमन्यु कुमार सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि ग्राम बिशनपुर स्थित 16 बिस्वा जमीन को उन्होंने अहमद अली से खरीदी थी। लेकिन आरोपी अहमद अली ने जाली दस्तावेज तैयार कर उसी भूमि का आधा हिस्सा अहमदपुर गांव निवासी सुमित्रा को बेच दिया था। मामले में मलिहाबाद तत्कालीन तहसीलदार वंदना कुशवाहा, लेखपाल समेत छह को आरोपी बनाया था।

लोडर चालक पर रिपोर्ट दर्ज

अमृत विचार, सरोजनीनगर : बिजनौर थाना क्षेत्र में 14 फरवरी को लोडर वाहन की टक्कर से घायल हुए बाइक सवार आशीष उपाध्याय के मामले में पिता सुनील उपाध्याय निवासी न्यू रहीमाबाद सैन्यपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। घायल का इलाज उतरटिया स्थित प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है।

निवेश के नाम पर दो से षंटे 34.86 लाख

अमृत विचार, लखनऊ: शेयर ट्रेडिंग व क्रिप्टो में निवेश के नाम पर साइबर जालसाजों ने रेकमर्मी समेत 34.86 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ितों ने साइबर फ्राडम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस्केटर साइबर थाना बृजेश कुमार यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। इंडियनगैर के सेक्टर-11 स्थित समता नगर निवासी इंदल बहादुर सिंह दिव्यांग हैं। कुछ माह पहले आरोपी सिंह नाम की युवती ने द्वाइसप पर संपर्क किया। शेयर ट्रेडिंग मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 29.59 लाख रुपये ठग लिए। मुनाफा मांगने पर पीड़ित ने टालमटोल की।

भाजपा को हराना मतलब यूपी को बचाना: अखिलेश

एसआईआर के जरिए लोकतंत्र कमजोर करने की साजिश का आरोप

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा को हराना बेहद जरूरी है, क्योंकि भाजपा को हराने का अर्थ यूपी को बचाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है और आज भ्रष्टाचार, अपराध व कमीशनखोरी चरम पर है। यह सरकार हर वर्ग को अपमानित कर रही है और सामाजिक अन्याय व नफरत की प्रतीक बन चुकी है।

गुरुवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय, लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा कार्यकर्ताओं को बहुत समझदारी से काम करना होगा। उन्होंने आगाह किया कि भाजपा की साजिशों से सतर्क और सजग रहना जरूरी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एसआईआर (मतदाता सूची पुनरीक्षण) के नाम पर बड़े पैमाने पर घपला कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि पीडीए वर्ग के मतदाताओं का वोट कटवाने के लिए हर जिले में लाखों नोटिस भेजे जा रहे हैं, ताकि लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा सके। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे हर पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने में मदद करें और

2027 में सजग और सतर्क रहकर काम करें सपा कार्यकर्ता

'पीडीए दिवस' नई शुरुआत

अखिलेश यादव ने कहा कि 'पीडीए दिवस' पीडीए समाज के उन महान व्यक्तित्वों को समर्पित है, जिन्होंने शोषित-पीड़ित समाज के सम्मान और बराबरी के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि जो पीड़ित, वही पीडीए। हम सब एक हैं।

पूरी प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों और नौजवानों के साथ छल कर रही है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौतों से किसानों को भारी नुकसान होगा और खेती-किसानी बर्बाद हो सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह आर्थिक आत्मसमर्पण है, जिससे दालों, बाजरा और अन्य फसलों पर प्रतिकुल असर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की आर्थिक नीतियां जनविरोधी हैं। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे गरीब और गरीब होता जा रहा है, जबकि अमीर और अमीर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में विकास कार्य किए, नौजवानों को लैपटॉप देकर तकनीकी रूप से सशक्त बनाया। सपा की सरकार बने पर किसानों को सही कानून, बेरोजगारी खत्म करने और दाम बांधो नीति लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा।

सपा दलित, पिछड़ा व अल्पसंख्यक विरोधी

अमृत विचार, लखनऊ: सपा मुखिया अखिलेश यादव बसपा संस्थापक काशीराम के जन्म दिवस को पीडीए दिवस मनाए जाने की बात कहकर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तीखा तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सपा का चाल-चरित्र और हेहरा पहले जैसा ही है। सपा का नेतृत्व पहले से ही दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी है। जन्ता इन इनकी सच्चाई समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि सपा द्वारा पीडीए की राजनीति केवल दिखावा है। सपा ने सता में रहते हुए दलितों, पिछड़ों और गरीबों के हितों की अनदेखी की। बसपा सरकार में कासमगंज जिले का बसपा संस्थापक के नाम पर काशीराम नगर रखा गया था, वहीं सहारनपुर के मेडीकल कालेज का नाम भी बसपा संस्थापक के नाम पर था। लेकिन सपा सरकार ने आते ही उनके नाम बदल दिए। अब वह काशीराम के जन्म दिन पीडीए दिवस मनाने का ढोंग कर रही है। इसी तरह बसपा ने लखनऊ में उर्दू-फारसी, अरबी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, लेकिन अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता के चलते सपा सरकार ने उसका भी नाम बदल दिया। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह 1993 और 1995 के दौर की घटनाएं जन्ता भूली नहीं है। सपा ने बहुजन आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया। अब भी सामाजिक समीकरणों का इस्तेमाल कर रही है।

निर्वाचन कार्य है लोकतंत्र की मजबूती का आधार: रिणवा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों और उनके बूथ लेवल एजेंटों से कहा कि वह अधिक से अधिक नए और युवा वोटर्स को जोड़ने का काम करें। मतदाता का फोटो पहचान पत्र, फोटो, नाम, पता और उम्र सही दर्ज करें। निर्वाचन कार्य लोकतंत्र की मजबूती का आधार है और बीएलओ सच्चे डेमोक्रेसी वॉरियर्स हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को आगरा के आयुक्त सभागार में एसआईआर की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बैठक कर अधिकारियों और बीएलओ को विधानसभावार डिजिटाइज

बिजली दरों में कमी होने से उपभोक्ताओं को होगा

141.20 करोड़ का लाभ

अमृत विचार, लखनऊ : पावर कॉर्पोरेशन द्वारा फरवरी में विद्युत उपभोक्ताओं से की गई दस फीसदी की अतिरिक्त वसूली के मामले में बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश भर से वसूला गया करीब 141 करोड़ रुपए अब उपभोक्ताओं को वापस दिया जाएगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि फरवरी-26 माह में विभाग ने उपभोक्ताओं से 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार वसूल किया था। इसके खिलाफ उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में जोरदार विरोध दर्ज किया था। इसके चलते मार्च-26 में 2.42 प्रतिशत बिजली दर में कमी कर दी गई।

सीईओ ने आगरा में किया बूथों का निरीक्षण, राजनीतिक दलों के साथ की बैठक

एसआईआर की समीक्षा के दौरान उकृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ और अधिकारी किए सम्मानित

फार्म, ईपी रेशियो, जेंडर रेशियो, अनुपस्थित, मृतक, स्थानांतरित व डुप्लीकेट मतदाताओं के विवरण के साथ ही फॉर्म-6, 6ए, 7 और 8 की प्रविष्टियों के बारे में विस्तार से जाना। निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नोटिस जनरेशन, सुनवाई, 1950 हेल्पलाइन, बुक-ए-कॉल-विद बीएलओ और एनजीएसपी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रगति के बारे में पता किया।



आगरा में गुरुवार को एसआईआर की समीक्षा करते मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा सूरसदन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और उनके द्वारा बनाए गए बीएलए के साथ भी संवाद किया। मतदाता केन्द्रों का भी निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान कमिश्नर एवं रोल प्रेक्षक नागेन्द्र प्रताप और जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द मलपा बंगारी समेत एसआईआर के कार्य में लगे सभी अधिकारी मौजूद रहे।

8 मार्च तक सभी विद्यालयों में छात्राओं के बन जाएं अलग शौचालय : शर्मा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: अपर मुख्य सचिव (बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेन शर्मा ने परिषदीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं और शैक्षिक गुणवत्ता को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में 8 मार्च तक छात्राओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।

गुरुवार को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि छात्राओं की सुविधा, स्वच्छता और गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिन विद्यालयों में यह

अपर मुख्य सचिव ने की समीक्षा, परीक्षा, पीएम श्री योजना और पोषण व्यवस्था पर जोर

व्यवस्था अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, वहां तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूरा कराया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री (पीएम श्री) योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों में गतिविधियों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी दिनों में परिषदीय विद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं के संचार, पारदर्शी और समयबद्ध आयोजन के लिए सभी तैयारियां समय से पूरी करने को कहा। अपर मुख्य सचिव ने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत बच्चों को नियमित, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर

दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और वितरण की सतत निगरानी की जाए। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), निर्माणधीन कार्यों, प्री-प्राइमरी शिक्षा, बाल वाटिका और शिक्षण गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि समेकित शिक्षा के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों को सहायक उपकरणों का वितरण समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे बिना किसी बाधा के शिक्षा ग्रहण कर सकें। बैठक में पाठ्यपुस्तकों को आपूर्ति, बुलाई और समय से वितरण, विद्यालयों में फर्नीचर की उपलब्धता, स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब के प्रभावी उपयोग तथा उनके अनुश्रवण को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।

रेलयात्री कृपया ध्यान दें!

होली विशेष रेलगाड़ियाँ-2026 की संख्या में वृद्धि

रेलयात्रियों की सुविधा के लिए आगामी होली त्यौहार के दौरान पहले से ही घोषित अनेक होली विशेष रेलगाड़ियों के अलावा रेलवे द्वारा निम्नलिखित होली त्यौहार विशेष रेलगाड़ियों का भी संचालन किया जायेगा, जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

04088/04087 नई दिल्ली - पटना जं. - नई दिल्ली		10 फरें	
रेलगाड़ी सं. 04088	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04087	प्रस्थान
आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
---	14:30	नई दिल्ली	09:10
10:45	---	पटना जं.	12:05

04088 नई दिल्ली से दिनांक 27.02.2026 तक (प्रतिदिन) और 04087 पटना जं. से दिनांक 28.02.2026 से 04.03.2026 तक (प्रतिदिन)		08 फरें	
रेलगाड़ी सं. 04056	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04055	प्रस्थान
आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
---	18:05	आनन्द विहार(टर्मि.)	06:35
10:10	---	बलिया	14:00

04056 आनन्द विहार(टर्मि.)-बलिया-आनन्द विहार(टर्मि.)		08 फरें	
रेलगाड़ी सं. 04056	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04055	प्रस्थान
आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
---	18:05	आनन्द विहार(टर्मि.)	06:35
10:10	---	बलिया	14:00

04664/04663 अमृतसर - पटना जं. - अमृतसर		06 फरें	
रेलगाड़ी सं. 04664	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04663	प्रस्थान
आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
---	09:45	अमृतसर	20:00
02:35	02:45	लखनऊ	03:45
13:30	---	पटना जं.	16:00

04026/04025 आनन्द विहार(टर्मि.)-गोरखपुर-आनन्द विहार(टर्मि.) विशेष रेलगाड़ी (प्रतिदिन)		08 फरें	
रेलगाड़ी सं. 04026	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 04025	प्रस्थान
आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
---	21:05	आनन्द विहार(टर्मि.)	06:20
12:00	---	गोरखपुर	14:00

01302 हजरत निजामुद्दीन-कलबुरगि विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ी (प्रतिदिन)		01 फरें	
रेलगाड़ी सं. 01302	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 01301	प्रस्थान
आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
---	11:10	हजरत निजामुद्दीन	---
08:30	---	कलबुरगि	---

02569/02570 दरभंगा-नई दिल्ली-दरभंगा विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ी (प्रतिदिन)		61 फरें	
रेलगाड़ी सं. 02569	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 02570	प्रस्थान
आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
---	06:30	दरभंगा	10:00
04:00	---	नई दिल्ली	12:15

02563/02564 बरौनी जं.-नई दिल्ली-बरौनी जं. विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ी (प्रतिदिन)		61 फरें	
रेलगाड़ी सं. 02563	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 02564	प्रस्थान
आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
---	07:40	बरौनी जं.	15:10
05:10	---	नई दिल्ली	17:55

02569/02570 दरभंगा-नई दिल्ली-दरभंगा विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ी (प्रतिदिन)		61 फरें	
रेलगाड़ी सं. 02569	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 02570	प्रस्थान
आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
---	06:30	दरभंगा	10:00
04:00	---	नई दिल्ली	12:15

01302 हजरत निजामुद्दीन-कलबुरगि विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ी (प्रतिदिन)		01 फरें	
रेलगाड़ी सं. 01302	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 01301	प्रस्थान
आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
---	11:10	हजरत निजामुद्दीन	---
08:30	---	कलबुरगि	---

02569/02570 दरभंगा-नई दिल्ली-दरभंगा विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ी (प्रतिदिन)		61 फरें	
रेलगाड़ी सं. 02569	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 02570	प्रस्थान
आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
---	06:30	दरभंगा	10:00
04:00	---	नई दिल्ली	12:15

02569/02570 दरभंगा-नई दिल्ली-दरभंगा विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ी (प्रतिदिन)		61 फरें	
रेलगाड़ी सं. 02569	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 02570	प्रस्थान
आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
---	06:30	दरभंगा	10:00
04:00	---	नई दिल्ली	12:15

02569/02570 दरभंगा-नई दिल्ली-दरभंगा विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ी (प्रतिदिन)		61 फरें	
रेलगाड़ी सं. 02569	स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 02570	प्रस्थान
आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
---	06:30	दरभंगा	10:00
04:00	---	नई दिल्ली	12:15

जिलाध्यक्ष जल्द घोषित करें अपनी कार्यकारिणी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संगठनात्मक बैठक की। बैठक में जिला स्तर पर ढांचे को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। जिलाध्यक्षों को अपनी-अपनी जिला कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पार्टी नेतृत्व ने कहा कि संगठनात्मक मजबूती के लिए जिला इकाइयों का गठन प्राथमिकता पर किया जाए। यदि प्रक्रिया तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ती है, तो मार्च के प्रथम पखवाड़े तक

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने वीसी से बैठक कर निर्देश

जिला कार्यकारिणियों की घोषणा की जा सकती है। इससे पहले जिलाध्यक्षों को स्थानीय स्तर पर संतुलन, संगठनात्मक अनुभव और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए टीम गठित करने को कहा गया है। पार्टी के भीतर इसे आगामी चुनावी और संगठनात्मक गतिविधियों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। जिला कार्यकारिणियों के गठन से बूथ से लेकर जिला स्तर तक संगठन को और सक्रिय व प्रभावी बनाने की रणनीति मानी जा रही है।

भाजपा ने घोषित किए बचे 14 जिलाध्यक्ष

अमृत विचार, लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने गुरुवार को संगठन पर्व के तहत बचे हुए 14 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही प्रदेश में सभी जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा पूरी हो गई है। लंबे समय से अपने खास को जिलाध्यक्ष बनाने की पेशवादी में घोषणा अटकी हुई थी। प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि संगठनात्मक ढांचा अब पूरी तरह तैयार हो गया है, जिससे आगामी चुनावी रणनीति को और धार मिलेगी। घोषित जिलाध्यक्षों में शामिलों से रामजी लाल कश्यप, अमररोहा से उदय गिरी गोरवाणी, सहारनपुर जिला से अजीत सिंह राणा, बागपत से नीरज शर्मा, पीलीभीत से गोकुल प्रसाद मौर्य, लखीमपुर से अरविंद गुप्ता, गोंडा से इकबाल बहादुर तिवारी, अयोध्या जिला से राधेश्याम त्यागी, अयोध्या महानगर से कमलेश श्रीवास्तव, मिर्जापुर से लाल बहादुर सरोज और सिद्धार्थनगर से दीपक मौर्य को कमान सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नव नियुक्त जिलाध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाना और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी।

आरआईडीएफ परियोजनाओं में तेजी लाएं

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: ग्रामीण अवसंरचना विकास को गति देने के लिए मुख्य सचिव एसपी गोयल ने आरआईडीएफ (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि) से वित्त पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यदायी विभाग नाबार्ड को प्रतिपूर्ति दावे, परियोजना स्वीकृति और परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र (पीसीआर) तय समयसीमा में अनिवार्य रूप से भेजें। वित्तीय वर्ष 2025-26 से संबंधित हाई पावर कमेटी की चतुर्थ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि

नाबार्ड को प्रतिपूर्ति दावे व पीसीआर समय से भेजने के निर्देश

दस्तावेजों में देरी से त्रुटि संवितरण और परियोजनाओं की गति प्रभावित होती है। उन्होंने नाबार्ड और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि किसी भी स्तर को विलंब देना नहीं की जाएगी। बैठक में पीवाईजी व स्लो मूविंग प्रोजेक्ट्स की अलग से समीक्षा हुई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इन परियोजनाओं का विस्तृत ब्योरा तत्काल नाबार्ड को भेजा जाए, ताकि अड़चनों की पहचान कर उन्हें दूर किया जा सके। उन्होंने कहा

कि लक्ष्य केवल स्वीकृति नहीं, बल्कि समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करना है। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि सभी कार्यदायी विभाग अपनी परियोजनाओं की क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट नियमित रूप से नाबार्ड को प्रेषित करें, जिससे परियोजनाओं की रीयल-टाइम निगरानी संभव हो सके और किसी भी स्तर पर विलंब को तुरंत पकड़ा जा सके। इससे पूर्व नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक पंकज कुमार ने अंवारत कराया कि चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण अवसंरचना विकास को प्राथमिकता देते हुए 3000 करोड़ रुपये के त्रुटि संवितरण का लक्ष्य रखा गया है।

ऑटो से चोरी करने वाला चालक गिरफ्तार

अमृत विचार, लखनऊ: बंद मकानों का ताला तोड़कर चोरी करने वाले ऑटो चालक को मड़ियांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल दो अपचारी को भी पकड़ा है। आरोपियों के पास से करीब चार लाख के जेवर, दस मोबाइल, 18,240 रुपये व चोरी में प्रयुक्त ऑटो बरामद हुआ है। पुलिस ने चोरी की दो घटनाओं का खुलासा किया है। एडीसीपी उत्तरी त्रुटि रूपवान ने बताया कि 12 फरवरी को द्वारिकापुरी कॉलोनी में शिवम मिश्रा और 18 फरवरी को एक अन्य घर में चोरी हुई थी। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में एक ऑटो कैद हुआ था।

खेतीबाड़ी होली पर मिलेगा कृषि यंत्रों पर अनुदान का तोहफा, 4 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन

किसानों के जीवन में खुशहाली का रंग भरेगी सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: होली के पर्व पर किसानों की आय और खेती की क्षमता बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों को अनुदान पर आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने जा रही है। इसके लिए बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 4 मार्च तक चलेगी। इच्छुक किसान कृषि विभाग की वेबसाइट www.agridarshan.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।



कृषि विभाग के अनुसार यह पहल किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर खेती को लाभकारी, समयबद्ध और कम लागत वाली बनाने की दिशा में अहम कदम है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक, कृषि ड्रेन, विभिन्न एकल कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा

रहे हैं। इसके अलावा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विशेष कृषि यंत्र और प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रांप रेज्यू योजना के तहत भी आवेदन किए जा सकते हैं। साथ ही त्वरित मकवा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैच ड्रायर और मेज सेलर के

मवेशी को बचाने में तालाब में गिरी फार्च्यूनर, कारोबारी की मौत

संवाददाता, हरदोई

अमृत विचार। गाजियाबाद के केबिल कारोबारी अपने दोस्त के बेटे की बारात में शामिल होने के बाद दोस्तों के साथ फार्च्यूनर कार से वापस लौट रहा था। उसी बीच शाहाबाद-पिहानी रोड पर सामने आए मवेशी को बचाने में बेकाबू हुई फार्च्यूनर तालाब में जा गिरी। पीछे से आ रहे बारातियों ने तालाब में पड़ी फार्च्यूनर कार के इंटीकेटर जलते देखे तो हादसे की जानकारी हुई। लोगों ने तत्काल सभी को बाहर निकाल कर सीएचसी शाहाबाद पहुंचाया। जहां से केबिल कारोबारी को मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है।



आनंद की फाइल फोटो।

था, गाजियाबाद के साहिबा बाद में केबिल का कारोबार करता था और पत्नी नंदिनी सिंह दोनों बच्चों के साथ गांव में हैं। मंगलवार को आनंद की 4 महीने की बच्ची का अन्नप्राशन संस्कार था, साथ ही मंगलवार को दोस्त बृजेश सिंह के बेटे की बारात थी, उसी के चलते आनंद गांव आया हुआ था। मंगलवार को आनंद अपनी फार्च्यूनर कार से बारात के साथ मझिला थाने के री गांव गया हुआ था, उसके साथ गांव निवासी पवन सिंह, दौली निवासी सुनील और दिल्ली निवासी ड्राइवर मोहित था। रात में वह अपने साथियों के साथ वापस लौट रहा था, उसी बीच शाहाबाद-पिहानी रोड पर री गांव से कुछ दूर पहुंचते ही सामने से मवेशी आ गया, कार चला रहे आनंद ने उसे बचाने की कोशिश की, उसी बीच बेकाबू हुई फार्च्यूनर कार सड़क किनारे तालाब में जा गिरी, बारात में शामिल बाराती पीछे से पहुंचे। लोगों तुरंत उसमें फंसे लोगों को बाहर निकाल कर सीएचसी शाहाबाद पहुंचाया, जहां से आनंद को मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया, जहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई।

वायरलेस सेट के काम नहीं करने पर भड़के आईजी रेलवे

उन्नाव, अमृत विचार। गुरुवार सुबह आईजी रेलवे ने उन्नाव जंक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान तकनीकी खामियों को लेकर उनका कड़ा रुख देखने को मिला। विशेषकर वायरलेस सेट के काम न करने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। आईजी रेलवे सुबह 11 बजे जंक्शन पहुंचे। उन्होंने दौरे की शुरुआत हेल्थ यूनिट से की, जहां आरपीएफ व जीआरपी के जवानों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने सभी जवानों को पूरी निष्ठा के साथ कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प दिलाया। जब आईजी आरपीएफ थाने पहुंचे तो वहां रखे वायरलेस सेट की कार्यक्षमता जांचने के लिए उन्होंने स्टाफ को बुलाने का प्रयास किया। वायरलेस काम न करने पर जब उन्होंने कारण पूछा तो इंस्पेक्टर ने चार्जिंग न होने की बात कही। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई।

पूर्वांचल रेलवे	
भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/कार्य, वारंटे मुख्य कारखाना प्रबन्धक यांत्रिक कारखाना गोरखपुर द्वारा नीचे लिखे कार्य के लिए ऑनलाईन (ई-टेंडरिंग) के माध्यम से खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। क्र.सं. 1. ई-निविदा सूचना सं. एवं निविदा कार्य का विवरण: टेंडर नं.: '51-जीकेपी-एमडब्ल्यूए-2025-26' 'सप्लाय एण्ड एलिकेशन ऑफ सिनाइट ग्राफिकल्स फिल्म ऑन द साइड पैनेल एण्ड पॉइंटिंग ऑफ रूफ एण्ड इण्ड पैनेल विद डीकेलिंग अलग विद स्क्रिपिंग, क्लीनिंग एण्ड पॉइंटिंग ऑफ अन्डरफ्रेम ऑफ रैक 09 एण्ड 24 ऑफ वंदे भारत कोचसे इन मेकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर'। अनुमानित लागत (₹ में): ₹48,80,486.40; धरोहर राशि (₹ में): ₹97,600/-; निविदा समान की तिथि एवं अवधि: 11:00 बजे, 18.03.2026 निविदा प्राप्त का मूल्य: ₹ शून्य। संविदा की अवधि: 12 माह। उपरोक्त ई-निविदाओं का पूर्ण विवरण एवं निविदा में भाग लेने हेतु भारतीय रेल की वेबसाइट संख्या http://www.irps.gov.in पर देखें।	
उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/कार्य मुजाबि/यांत्रिक-144 गोरखपुर	ट्रेनों में बीडी/शिफ्ट न पिचें

जर्मन युवक संग हिंदू रीति-रिवाज से रचाई शादी

बाराबंकी, अमृत विचार : जनपद की बेटे रुलन वर्मा की विदेशी लड़के से शादी की चर्चा जोरों पर है। रेलवे में असिस्टेंट इंजीनियर राज कुमार वर्मा की पुत्री रुलन वर्मा उच्च शिक्षा के लिए विदेश गई थीं। फ्रांस से पीएचडी करने के बाद वह वर्तमान में ऑस्ट्रिया के वियाना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर व वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात जर्मनी के एक युवक से हुई, जो दोस्ती से ओमो बदकर प्रेम में बदल गई। विवाह के लिए दूहा अपने परिवार के 16 सदस्यों के साथ विशेष रूप से भारत पहुंचे। शहर के होटल रॉयल रिलाइट में आयोजित समारोह में हल्दी, मेहंदी और जयमाला सहित सभी रस्में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुई। भारतीय शेरवानी पहने विदेशी दूहा कार के सनरूप से निकलकर भारतीय गीतों पर थिरकता नजर आया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। दुल्हन के चाचा आरसी पटेल ने इसे जनपद के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि जर्मनी से आए मेहमानों को भारतीय परिधान, खासकर साड़ियां और यहां का खान-पान बेहद पसंद आया।



जयमाला डालती रुलन वर्मा।

अमृत विचार

लखनऊ से युवती को लाने वाला गिरफ्तार

बाराबंकी, अमृत विचार : नशे में युवती के मित्रों के केस में पुलिस ने उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि युवक व युवती दो साल से एक ही जगह काम करने की वजह से संपर्क में थे। ग्राम अझियापुर के पास एक युवती सदिग्ध हाल में सड़क किनारे मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को युवती नशे में मिली। उसे मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। उसी दिन थाने पहुंची लखीमपुर की मूल निवासी व पीड़िता की बहन ने आरोप लगाया कि लखनऊ में एक पेट्रोल पंप पर काम कर रही बहन को अंकिता तिवारी लेकर आया था।

कार्यालय उपजिलाधिकारी लम्भुआ, सुलतानपुर।	
पत्रांक	821 / २०२०-मत्स्यपालन आवंटन / 2025-26 दिनांक 22.02.2026
तहसील के तालाबों के आवंटन की विज्ञप्ति	
उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 की धारा 61 के अन्तर्गत 0.20हे० से 2.00हे० तक के तथा 2.00हे० से बड़े तालाबों का आवंटन/नीलामी तहसील-लम्भुआ के समागार में सुबह 11.00बजे से सायं 3.00बजे तक किया जायेगा। मत्स्य पालन के पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति समय से उपस्थित होकर आवंटन की कार्यवाही में भाग लेने का कष्ट करें। दस वर्षीय मत्स्य पालन पट्टा दिये जाने के आवंटन/नीलामी की कार्यवाही हेतु तालाबों का विवरण, नीलाम अधिकारी तथा ग्राम निम्नासुर है।	
नीलामी स्थल:- तहसील-लम्भुआ के समागार में सुबह 11.00बजे से सायं 1.00बजे तक	
नीलामी अधिकारी:- तहसीलदार/नायब तहसीलदार लम्भुआ, जनपद सुलतानपुर।	
आरक्षित बोली की धनराशि:- (0.20 हे० से 2.00हे० तक 5000/- एवं 2.00हे० से बड़े तालाबों का ₹० 10000/-प्रति हे०)।	
तालाबों का विवरण निम्नवत् है:-	

क्र०	ग्राम का नाम	तालाब/पोखरों का विवरण	आरक्षित बोली की धनराशि (प्रति हे० रु०में)	नीलामी की तिथि	नीलामी स्थल	नीलाम अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	रामगढ़	306	1.385	6925	23.03.2026	तहसील समागार
2	रामगढ़	835ग	1.062	5310	"	"
3	शेषनपुर	636	1.141	5705	"	"
4	दबरखा	23क	1.282	6410	"	"
5	ओझापुर	745	0.949	4745	"	"
6	पतीपुर	177	1.278	6390	"	"
7	अमारी	6क	1.068	5340	"	"
8	मीखनपुर	197ख	0.569	2845	"	"
9	असवा	81	0.739	3695	"	"
10	असवा	104	0.986	4930	"	"
11	बेलसौना	194	1.457	7285	"	"
12	बेलसौना	477	0.241	1205	"	"
13	भरसांर	163ख	1.43	7150	"	"
14	सुलतानपुर बेरो	38	1.556	7780	"	"
15	सुलतानपुर बेरो	60	1.126	5630	"	"
16	पलिया	287	1.977	9885	"	"
17	पलिया	453	1.757	8785	"	"
18	पीथीपुर	131ख	1.736	8680	"	"
19	पीथीपुर	340	0.544	2720	"	"
20	बंसतपुर	135	0.885	4425	"	"
21	बंसतपुर	331	1.139	5695	"	"
22	संमरी पुरुषोत्तमपुर	1711स	1.442	7210	"	"
23	लहिया जलपापुर	839	0.759	3795	"	"
24	संमरीकला	166	1.116	5580	"	"
25	संमरीकला	357इ	1.455	7275	"	"

क्र०	ग्राम का नाम	तालाब/पोखरों का विवरण	आरक्षित बोली की धनराशि (प्रति हे० रु०में)	नीलामी की तिथि	नीलामी स्थल	नीलाम अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	कुसेला	60ख	0.961	4805	23.03.2026	तहसील समागार
27	सरायजुझार	71मि	1.439	7195	"	"
28	सरायजुझार	80	1.906	9530	"	"
29	मलाकतुलापुर	369	0.727	3635	"	"
30	नैवादानपुर	463	0.777	3885	"	"
31	मधुपुर	83	0.759	3795	"	"
32	पुरैना	287	0.714	3570	"	"
33	लोदीपुर	89	0.873	4365	"	"
34	लोदीपुर	110	1.764	8820	"	"
35	लोदीपुर	161	0.835	4175	"	"
36	उचाहरा	512	0.658	3290	"	"
37	रामपुर	44मि	1.027	6350	"	"
38	रामपुर	230	0.417	2085	"	"
39	रामपुर	474	0.502	2520	"	"
40	ओसानपुर	526	0.544	2710	"	"
41	रघुनाथपुर	418	0.911	4555	"	"
42	गारवपुर	815	1.644	8220	"	"
43	गारवपुर	816	1.012	5060	"	"
44	गारवपुर	832	0.923	4615	"	"
45	गारवपुर	833	0.923	4615	"	"
46	गारवपुर	1008	1.397	6985	"	"
47	गारवपुर	1071	0.938	4690	"	"
48	देलहा	271ज	1.752	8760	"	"
49	सोनबरसा	57क	1.268	6340	"	"
50	मनोरथपुर	1	0.772	3860	"	"
51	दहेवागोपालपट्टी	156	1.892	9460	"	"
52	जदुपुर	190ग	0.986	4930	"	"
53	खड्डवान	126	0.943	4715	"	"
54	भरखरे	106ख	1.423	7115	"	"
55	भरखरे	604ख	0.822	4110	"	"
56	भरखरे	621ख	0.784	3920	"	"
57	हड्डहा	213	1.163	5815	"	"
58	रुदौली	349	0.215	1075	"	"
59	रामगढ़	1285	1.252	6260	"	"
60	मानापुर	48	0.708	3540	"	"
61	कांडर	165ड	2.972	29720	"	"
62	बैजीपुर	411	4.509	45090	"	"
63	गड्डहा	8	1.138	5690	"	"
64	खसडे	101क	0.759	3795	"	"
65	खसडे	108	1.026	5130	"	"

क्र०	ग्राम का नाम	तालाब/पोखरों का विवरण	आरक्षित बोली की धनराशि (प्रति हे० रु०में)	नीलामी की तिथि	नीलामी स्थल	नीलाम अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
66	खसडे	524	0.696	3480	24.03.2026	तहसील समागार
67	खसडे	856क	1.164	5820	"	"
68	बालमपुर	53ख	1.29	6450	"	"
69	बालमपुर	1319	1.379	6895	"	"
70	बालमपुर	1933ग	1.272	6360	"	"
71	कल्याणपट्टी	226	0.848	4240	"	"
72	कल्याणपट्टी	433	0.885	4425	"	"
73	होलापुर	281क	0.873	4365	"	"
74	भौरी	27	0.685	3425	"	"
75	मुकुन्दपुर	59क	1.088	5440	"	"
76	मुकुन्दपुर	319	1.05	5250	"	"
77	कनपुर	312	0.638	3190	"	"
78	शिवगढ़	251	0.253	1265	"	"
79	शिवगढ़	159	0.847	4235	"	"
80	प्रतापपुर कमैचा	808	1.075	5375	"	"
81	दबरपुर	3	1.708	8540	"	"
82	दबरपुर	320	0.986	4930	"	"
83	रामनगर	348ख	1.771	8850	"	"
84	आनापुर नारायणगंज	706	1.015	5075	"	"
85	पकडी खुर्द	405	1.442	7210	"	"
86	कोथरा खुर्द	286	1.543	7765	"	"
87	कोथरा खुर्द	448	1.657	8285	"	"
88	कोथरा खुर्द	487	1.113	5565	"	"
89	कोथरा कला	318इ	0.904	4520	"	"
90	धुरीपुर	614ख	1.808	9040	"	"
91	गडमा कोइरीपुर	185ख	1.24	6200	"	"
92	अरजो	129	1.584	7920	"	"
93	अरजो	299	1.503	7510	"	"
94	इंशीपुर	173ग	1.791	8955	"	"
95	मानापुर	75	1.113	5565	"	"
96	पुनीमोमपट्टी	280ख	1.467	7335	"	"
97	राजपुर	5	0.993	4965	"	"
98	राजपुर	72ख	1.638	8190	"	"
99	खानपुर	329	0.901	4505	"	"
100	खानपुर	330	0.544	2720	"	"
101	जुझारा	1	0.468	2340	"	"
102	हंसोनाथपुर	95मि	0.891	4455	"	"
103	जगन्नाथपुर	51	0.658	3290	"	"
104	आनापुर मीखीपुर	324क	0.658	3290	"	"
105	सुलतानपुर	140	0.202	1010	"	"

क्र०	ग्राम का नाम	तालाब/पोखरों का विवरण	आरक्षित बोली की धनराशि (प्रति हे० रु०में)	नीलामी की तिथि	नीलामी स्थल	नीलाम अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
106	राजा उमरी	13ख	1.245	6225	24.03.2026	तहसील समागार
107	राजा उमरी	484ख	0.481	2405	"	"
108	खुशीपुर	908	0.838	4190	"	"
109	रामपुर	436	1.077	5385	"	"
110	रामपुर कुमियान	621	1.182	5910	"	"
111	तेरये	661मि	0.306	1530	"	"
112	तेरये	760	0.360	1800	"	"
113	तेरये	164ख	0.253	1265	"	"
114	सुरंगानपट्टी	110घ	1.012	5060	"	"
115	माधोपुर	64	0.443	2215	"	"
116	माधोपुर	66मि	1.518	7590	"	"
117	जहानियापुर	3</				

मोदी ने भारतीय प्रवासियों को बताया लिविंग ब्रिज

यरुशलम, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऐतिहासिक इजराइल यात्रा के दौरान गुरुवार को यरुशलम में भारतीय मूल के यहूदी समुदाय के सदस्यों से आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने इस समुदाय को भारत और इजराइल के बीच एक लिविंग ब्रिज (जीवंत सेतु) करार देते हुए कहा कि वे न केवल इजराइल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक पटल पर संजोए हुए हैं। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत को अपनी इस यहूदी संतान पर गर्व है, जो सदियों से बिना किसी भेदभाव के भारत का अभिन्न हिस्सा रही है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा



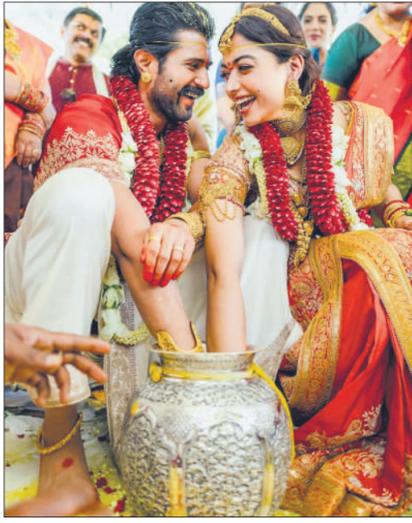
भारतीय प्रवासियों से बात करते प्रधानमंत्री मोदी

सांस्कृतिक कार्यक्रम और 'आई लव माय इंडिया' की गूज

मुलाकात के दौरान एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग कलाकारों ने 'आई लव माय इंडिया' गीत पर प्रस्तुति दी। इस भावुक प्रस्तुति ने प्रधानमंत्री समेत वहां मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। पीएम मोदी ने कलाकारों की सराहना करते हुए कहा कि कला और संगीत की कोई सीमा नहीं होती और यह भारत-इजराइल की अटूट दोस्ती का सबसे सुंदर प्रतीक है। उन्होंने इजराइल में सेवा दे रहे भारतीय 'केयरगिवर्स' (देखभाल करने वालों) के श्रेय और साहस की भी प्रशंसा की, जिन्होंने युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सेवाएँ जारी रखीं।

कि इजराइल में भारतीय मूल के यहूदी समुदाय के साथ बातचीत करना सुखद रहा। भारत के प्रति उनका गहरा लगाव और इजराइल की प्रगति में उनका अटूट समर्पण वास्तव में प्रेरणादायक है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के 'बेने इजराइल', केरल के

'कोचिनी', कोलकाता के 'बगदादी' और पूर्वोत्तर के 'बनेई मेनाशे' समुदाय के इतिहास का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन गिने-चुने देशों में से एक है, जहाँ यहूदियों को कभी भी उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा।



राजस्थान के उदयपुर के बाहरी इलाके में आयोजित विवाह समारोह के दौरान अभिनेता रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा।

उदयपुर में संपन्न हुई फिल्म स्टार विरोश की शाही शादी

उदयपुर, एजेंसी। दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित सितारे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा गुरुवार को राजस्थान के उदयपुर में एक निजी और भव्य समारोह में विवाह के बंधन में बंध गए। पिछले सात वर्षों से चले आ रहे कयासों पर विराम लगाते हुए, इस जोड़े ने अपनी शादी की पहली आधिकारिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं।

इन तस्वीरों में रश्मिका पारंपरिक लाल साड़ी और स्वर्ण आभूषणों में नजर आईं, जबकि विजय ने ऑफ-व्हाइट धोती और लाल शॉल पहनकर अपने तेलुगु मूल की परंपराओं का सम्मान किया। उदयपुर के बाहरी इलाके में स्थित एक लज्जरी होटल में आयोजित इस समारोह में केवल दोनों परिवारों के सदस्य और करीबी मित्र ही शामिल हुए। शादी की रस्में पूरी तरह से

● रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बंधे विवाह बंधन में

पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुई। सुबह 10 बजे के शुभ मुहूर्त में तेलुगु रीति-रिवाजों के अनुसार मंजुशु विवाह हुआ, जबकि शाम को रश्मिका की विरासत का सम्मान करते हुए कोडवा (कूर्गी) परंपरा से दूसरा समारोह आयोजित किया गया। इस विवाह को उनके प्रशंसकों द्वारा दिए गए नाम 'द वेडिंग ऑफ विरोश' के रूप में सेलिब्रेट किया गया। विजय देवरकोंडा ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद भावुक संदेश साझा करते हुए लिखा, "मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी पत्नी बना लिया है।" रश्मिका ने भी शादी की तस्वीरें साझा करते हुए अपने पति के लिए अपना प्यार व्यक्त किया। उदयपुर में तीन दिनों तक चले इस उत्सव में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम थे।

वर्ल्ड ब्रीफ

मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 200 न्यायिक अधिकारी आएंगे

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए पड़ोसी राज्यों झारखंड और ओडिशा से करीब 200 न्यायिक अधिकारियों के जल्द ही बंगाल आने की संभावना है। निर्वाचन आयोग के विशेष सूची पर्यवेक्षक सुभ्रत गुप्ता ने गुरुवार को यह जानकारी साझा की। यह महत्वपूर्ण कदम उच्चतम न्यायालय के उस सुझाव के बाद उठाया जा रहा है, जो उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजोय पांडे को दिया था। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य अन्य राज्यों के निष्पक्ष अधिकारियों की मदद से मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को शिकारियों को दूर करना है।

ममता बनर्जी का आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज हैक

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज 'सोरासरी मुख्यमंत्री' हैक कर लिया गया है। इस हाई-प्रोफाइल डिजिटल सेंसॉर की बाद राज्य प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंधे मच गया है। गुरुवार को यह मामला सामने आने के बाद कोलकाता पुलिस के साइबर सेल ने तुरंत अज्ञात हैकरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पोर्टल का उपयोग सीधे जनता की शिकायतों और सुझावों के लिए किया जाता है, जिससे इसकी सुरक्षा को बेहद सचेतनता से देखा जाता है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, पेज पर कुछ सटिचिंग गतिविधियाँ देखी गईं, जिसके बाद विशेषज्ञों ने पाया कि अकाउंट का नियंत्रण अनधिकृत हाथों में चला गया है।

पत्नी की मौत पर याचिका, हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को गाजियाबाद के एक व्यवसायी की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने केन्द्र सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता रामवीर सिंह गोला का दावा था कि पिछले वर्ष नेपाल में 'जेन-जेड' विरोध प्रदर्शनों के दौरान काटमांडू में उनकी पत्नी की मृत्यु केन्द्र की कोटाही के कारण हुई थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पुरुषोत्तम कुमार कोरव ने स्पष्ट किया कि यह याचिका विचारणीय नहीं है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि इस मामले में कई विवादित तथ्य शामिल हैं, जिन्हें साबित करने के लिए विस्तृत सबूतों की आवश्यकता है।

बोझ और झंझट बन गए हैं न्यायाधिकरण

सीजेआई ने कहा- श्रीमान अटॉर्नी जनरल, न्यायाधिकरण आपकी रचना हैं और वे सिरदर्द बन गए हैं

नई दिल्ली, एजेंसी

देश में न्यायाधिकरणों के कामकाज पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वे बिना किसी "जवाबदेही के बोझ और झंझट" बन गए हैं। न्यायालय ने इस बात को लेकर चिंता जताई कि एक वित्तीय न्यायाधिकरण के तकनीकी सदस्य निर्णय लिखने का काम भी आउटसोर्स कर रहे थे।



● विधायी व्यवस्था के कारण उनके कामकाज का तरीका कोर्ट के लिए बनता रहा है चुनौती

विकसित करने का प्रयास कर रही है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह राष्ट्रीय हित में नहीं है कि न्यायाधिकरण किसी के प्रति जवाबदेह न हों।

पीठ ने कहा कि अदालत मौजूदा सदस्यों को कार्यकाल का एकमुश्त विस्तार देने की इच्छुक नहीं थी, लेकिन न्यायाधिकरणों में रिक्तियों को नहीं भरे जाने के कारण ऐसा करने के लिए विवश थी। सीजेआई ने कहा कि उनके पास एक महत्वपूर्ण न्यायाधिकरण के संबंध में विश्वसनीय जानकारी है, जो देश की अर्थव्यवस्था के कारण महत्वपूर्ण है और जहां तकनीकी सदस्य खुद फैसले नहीं लिख रहे थे।

सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने टिप्पणी की कि न्यायाधिकरण सरकार द्वारा बनाए गए हैं और वे बिना किसी जवाबदेही के अनियंत्रित होकर कार्य कर रहे हैं। न्यायालय पिछले साल के उस फैसले के मद्देनजर न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों सहित सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 को रद्द कर दिया गया था। पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. के. वेंकटरमणी से रिक्त पदों को तत्काल भरने के लिए कुछ व्यवस्था करने को कहा। साथ ही, पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान व्यवस्था के

अनुसार, टीडीएसएटी न्यायाधिकरण का एक तकनीकी सदस्य अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति पर अर्ध-न्यायिक निकाय का कार्यवाहक अध्यक्ष बन जाता है। न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण न्यायाधिकरणों में कोई कार्यात्मक संकट न हो, क्योंकि उसने ऐसी व्यवस्था पर आपत्ति जताई है जिसमें कोई तकनीकी सदस्य अध्यक्ष का पद संभाले।

सीजेआई ने कहा कि अब जिस तरह के आदेश हम देख रहे हैं, कुछ न्यायाधिकरणों को छोड़कर, ये संस्थाएं एक तरह से 'अनियंत्रित' हो गई हैं क्योंकि वे न तो न्यायापालिका के प्रति जवाबदेह हैं और न ही पृथ्वी पर किसी के प्रति जवाबदेह हैं।" अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने के लिए एक तंत्र

उन्होंने कहा, "ये तकनीकी सदस्य एक भी फैसला नहीं लिख रहे हैं, वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि न्यायिक सदस्य उनकी ओर से और उनके नाम पर फैसला लिखें। मुझे तो एक तकनीकी सदस्य की धृष्टता का भी पता है, जिसने एक न्यायिक सदस्य से अपने नाम से फैसला लिखने को कहा और उन्हें ब्लैकमेल किया कि

कनाडा के पीएम कार्नी आज से चार दिन की भारत यात्रा पर

नई दिल्ली, एजेंसी

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 27 फरवरी से 2 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। यहां प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से गुरुवार को जारी एक विज्ञापित के अनुसार कार्नी शुक्रवार को मुंबई पहुंचेंगे और वह वहां अगले दो दिन विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे।



इस दौरान वह भारत और कनाडा की कुछ प्रमुख कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों की विशेषज्ञों, नवप्रवर्तकों, शिक्षाविदों के साथ-साथ भारत में स्थित कनाडा के पेंशन फंड प्रमुखों के साथ वार्तालाप करेंगे। प्रधानमंत्री कार्नी पहली मार्च को राजधानी नई दिल्ली पहुंचेंगे 2 मार्च को मार्च को श्री मोदी के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों

युवक कांग्रेस के तीन कार्यकर्ता तीन दिन की पुलिस रिमांड पर

नई दिल्ली, एजेंसी

देश की राजधानी में अनांखे तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वाले भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के तीन कार्यकर्ताओं को दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इन कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक स्थान पर अमर्यादित आचरण करने और सुरक्षा घेरा तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अदालत से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

यह मामला तब शुरू हुआ जब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान इन तीन कार्यकर्ताओं ने अपनी कमीज उतारकर अर्ध-नग्न अवस्था में नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस का तर्क है कि इस तरह के प्रदर्शन से सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हुई और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया।

आतंकवाद का सामना करने के लिए सामूहिक संकल्प की आवश्यकता : जयशंकर

जिनेवा, एजेंसी

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद का कड़ा विरोध करता है और इस समस्या का सामना करने के लिए सामूहिक संकल्प की आवश्यकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) से आतंकवादी कृत्यों को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाने का आग्रह किया। जयशंकर यूएनएचआरसी के 61वें सत्र के दौरान एक कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि भारत संघर्ष, ध्रुवीकरण और अनिश्चिन्ता से ग्रस्त विश्व में साझा आधार खोजने और उसका विस्तार करने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा उदारता के बजाय संवाद, विभाजन के बजाय सहमति और संकीर्ण हितों के बजाय मानव-

सपनों की दुनिया में जी रहा है पाकिस्तान

जिनेवा/नई दिल्ली। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान के सपनों की दुनिया में जीने पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर का बजट इस्लामाबाद के आईएमएफ से हाथ ही में मांगे गए बेलआउट पैकेज से दोगुने से भी अधिक है। भारत ने पाकिस्तान को पीओके को खाली करने के लिए भी कहा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें नियमित सत्र के उच्च-स्तरीय खंड में भारत के 'जवाब देने के अधिकार' का उपयोग करते हुए, कहा कि निरंतर राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के माध्यम से क्षेत्र को अस्थिर करने के पाकिस्तान के प्रयासों के बावजूद, जम्मू-कश्मीर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ रहा है। सुश्री सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वह अपने गहराते आंतरिक संकटों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करें, न कि इस तरह के मंच पर आडंबरपूर्ण तरीके से उन्हें छिपाने का प्रयास करे।



केंद्रित विकास पर जोर दिया है। हम इस परिषद और संयुक्त राष्ट्र से आतंकवादी कृत्यों को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाने की अपेक्षा करते हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण इस समझ पर आधारित है कि किसी भी क्षेत्र

की असुरक्षा या किसी भी समूह का हाशिए पर होना अंततः सभी के अधिकारों को कमजोर करता है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की मानवीय सहायता भौगोलिक सीमाओं से अधिक सहानुभूति से प्रेरित रही है।

वायु प्रदूषण

चिंताजनक स्थिति यूपी की, यहां 9% व बिहार में केवल 13% आबादी ही किसी स्टेशन के 10 किमी दायरे में आती है

देश की 85% आबादी निगरानी तंत्र से बाहर

नई दिल्ली, एजेंसी

● 64% जिलों में प्रदूषण मापने का एक भी रीयल-टाइम केंद्र नहीं



निगरानी तंत्र का मौजूदा ढांचा

- **मैनुअल स्टेशन** : 419 शहरों में 966 स्टेशन हैं, जो सप्ताह में सिर्फ दो बार मापन करते हैं।
- **सतत निगरानी केंद्र** : 294 शहरों में 562 केंद्र हैं, जो प्रति घंटे रीयल-टाइम आंकड़ा देते हैं।

विशेषज्ञों के सुझाव:

- भविष्य की निगरानी व्यवस्था में महंगे उपकरणों के साथ कम लागत वाले सत्यापित सेंसर और सैटेलाइट आंकड़ों को जोड़ा जाए।
- विद्यालयों, अस्पतालों और उच्च जोखिम वाले औद्योगिक क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर केंद्र स्थापित किए जाएं।
- बदलते शहरी स्वरूप के अनुसार फुराने निगरानी केंद्रों का स्थान बदलकर उच्च प्रभाव बनाया जाए।

दिल्ली-चंडीगढ़ सुरक्षित, यूपी-बिहार सबसे पीछे

रिपोर्ट के अनुसार, निगरानी केंद्रों का वितरण बेहद असमान है। चंडीगढ़ और दिल्ली: चंडीगढ़ में 100% आबादी निगरानी दायरे में है, दिल्ली में केवल 3.5% आबादी ही इस सुरक्षा कवच से बाहर है। सबसे चिंताजनक स्थिति यूपी की है, जहां मात्र 9% आबादी और बिहार में केवल 13% आबादी ही किसी स्टेशन के 10 किमी दायरे में आती है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल: महाराष्ट्र में केंद्र अधिक हैं, लेकिन वे सिर्फ मुंबई, पुणे और नागपुर तक सीमित हैं। पश्चिम बंगाल में 19% कवरेज है, जबकि हंगुली और मुर्शिदाबाद जैसे घनी आबादी वाले जिलों में एक भी रीयल-टाइम केंद्र नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में देश का 'वायु गुणवत्ता सूचकांक' और प्रदूषण नीतियां केवल एक छोटे शहरी हिस्से के आंकड़ों पर आधारित हैं। बड़े भूभाग में प्रदूषण लोगों के जीवन का हिस्सा तो है, लेकिन सरकारी रिपोर्टों में दर्ज ही नहीं हो पाता।

'एस्प्टीन फाइलों' के जरिए ट्रंप ने पीएम मोदी को धमकाया: राहुल गांधी

कन्नूर, एजेंसी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुए हालिया व्यापार समझौते को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। केरल के कन्नूर जिले के पेरारूर में एक विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विवादित 'एस्प्टीन फाइलों' का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी को डराने-धमकाने के लिए किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी दबाव के चलते प्रधानमंत्री ने एक ऐसे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारतीय किसानों के हितों को भारी नुकसान पहुंचाएगा और उनके भविष्य को संकट में डाल देगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने झुकने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह समझौता देश की आर्थिक और कृषि बुनियाद को कमजोर करने जैसा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार इस बुनियादी सच्चाई को भूल गई है कि किसान ही भारत की असली ताकत और नींव हैं।

जनगणना के टूल्स में पारंगत होकर करे प्रयोग : विशाख जी

कार्यालय संवाददाता लखनऊ

अमृत विचार : जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में गुरुवार के कलेक्ट्रेट सभागार में 'जनगणना-2027' की तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई। चार्ज अधिकारियों का प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी ने जनगणना-2027 के लिए विकसित डिजिटल टूल्स जैसे कि सीएमएस/पोर्टल और एचएलबीसी का लाइव डेमो देखा। निर्देश दिए कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सर्वेक्षण के समय विशेष सावधानी बरती जाए। ब्लॉक गठन के दौरान क्षेत्र में छूट या दोहराव न हो। प्रशिक्षण का संचालन अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) व जिला जनगणना अधिकारी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जनगणना कार्य निदेशालय की टीम ने जनगणना के डिजिटल टूल्स के उपयोग पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया। जनगणना निदेशालय संयुक्त निदेशक एके सिंह सोमवंशी, सहायक निदेशक उपासना आदि ने तौर तरीके बताए।

कर्ज में डूबे फरीदपुर के व्यापारी ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दी

फरीदपुर। कर्ज में डूबे किराना व्यापारी ने विथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के रजक परसपुर में पहुंचकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यापारी का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। फरीदपुर नगर के मोहल्ला महादेव निवासी किशन लाल (46) की रामलीला मैदान के सामने किराने की दुकान है। परिजनों के अनुसार बुधवार को रोज की तरह किशनलाल अपनी दुकान खोलने के लिए घर से निकले और शाम तक वापस नहीं आए। परिजनों ने काफी तलाश किया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा फोन भी बन्द जा रहा था। परिवार के लोगों ने बताया किशन पर कर्ज होने के कारण कर्ज वापस के लिए तकादा करने वाले उसे परेशान करते थे।



शुक्रवार, 27 फरवरी 2026



स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है।
-महात्मा बुद्ध

आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का 'प्रहार'



विवेक सार्वेशा
अयोध्या

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को अपनी पहली राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति, 'प्रहार' जारी कर राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और निर्णायक बदलाव किया है। ये नीति ऐसे समय में जारी की गई है, जब देश सीमापार प्रयोजित आतंक, ड्रोन आधारित हमले, हथियारों की तस्करी, साइबर हमले और आतंकियों के स्लीपर सेल आदि गंभीर चुनौतियों का लगातार सामना कर रहा है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि 'भारत आतंकवाद को किसी खास धर्म, जाति, राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ता है।' देश लंबे समय से सीमा पार से 'प्रायोजित आतंकवाद' से प्रभावित रहा है, जिसमें 'जिहादी आतंकी संगठन और उनके फ्रंटल संगठन' हमलों की प्लानिंग करते रहते हैं और उन्हें अंजाम देते हैं।

डार्क वेब और क्रिप्टो-फाइनेंसिंग जैसे आधुनिक खतरे भी देश के लिए बड़ी चुनौती हैं। यह नीति जल, थल और वायु तीनों मोर्चों पर सुरक्षा को मजबूत करने और बुनियादी ढांचे की रक्षा करने पर जोर देती है। इसमें अल-कायदा को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) जैसे वैश्विक आतंकी समूहों का नाम लेते हुए कहा गया है कि उन्होंने स्लीपर सेल के जरिए भारत में हिंसा भड़काने की कोशिश की है, जबकि दूसरे देशों से काम करने वाले हिंसक आतंकीवादियों ने आतंकवाद को बढ़ावा देने की साजिशें रची हैं।

पहलगाय में आतंकियों के हाथों हुआ नरसंहार केवल निर्दोष लोगों के जीवन पर हमला नहीं था। यह भारत की अंतरात्मा पर भी किया गया आक्रमण था। इसके प्रत्युत्तर में भारत ने आतंकवाद रोधी कार्रवाई की नियम पुस्तिका के पुनर्लेखन का निर्णय लिया।

'प्रहार' का अर्थ है 'स्ट्राइक्स', जो भारत के 'जीरो-टॉलरेंस' दृष्टिकोण को एक मजबूत और सक्रिय ढांचा प्रदान करता है। यह नीति सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में

एक बड़ा कदम है। आतंकी संगठन जिस तरह लगातार संगठित हमले और गतिविधियां कर रहे हैं, उसे देखते हुए यह समय की मांग है कि इससे सख्ती से निपटा जाए और इसके लिए रणनीतियों में भी एक समन्वय हो। यही वजह है कि सात मुख्य स्तंभों पर आधारित 'प्रहार' में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में तालमेल बैठाने पर भी खासा जोर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने एकआईआर दर्ज करने से लेकर मुकदमा चलाने तक, जांच के हर स्तर पर कानूनी जानकारों को शामिल करने का सुझाव दिया है, ताकि अपराधियों के खिलाफ केस मजबूत हो सके।

इस नीति में आतंकवादी हमलों को होने से पहले ही रोकना। खतरे के अनुरूप त्वरित और कठोर जवाब। पूरे सरकारी दृष्टिकोण के साथ आंतरिक क्षमताओं को एक साथ लाना। विधि के शासन का पालन करते हुए कार्रवाई करना। कट्टरपंथ के कारणों को समाप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय और खुफिया जानकारी साझा करना। 'संपूर्ण-समाज' दृष्टिकोण के माध्यम से सुरक्षा को मजबूत करने पर खासा जोर दिया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि विदेश में मौजूद ग्रुप हमले करने के लिए लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और इलाके की जानकारी पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं।

'प्रहार' नीति न केवल आतंकवाद को एक आघातक कृत्य मानती है, बल्कि उसे एक व्यापक 'शत्रुतापूर्ण नेटवर्क' के रूप में देखती है। यह नीति 2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसी निर्णायक कार्रवाइयों के बाद के सुरक्षा परिदृश्य के अनुकूल है, जो पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद को कड़ी चुनौती देती है। भारत अब अपनी सुरक्षा नीति में रक्षात्मक से आक्रामक प्रतिरोध की ओर मजबूती से बढ़ गया है। यह नीति आतंकवाद के खिलाफ मोदी की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है।

आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी अपने सिद्धांत और उसके तीन

स्तंभ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। पहले प्रमुख स्तंभ में आतंकवादी घटनाओं का भारत की शर्तों पर निर्णायक उत्तर निहित है। भारत पर किसी भी आतंकवादी हमले का भारत की शर्तों पर ही करारा जवाब दिया जाएगा। देश आतंकवाद की जड़ों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इसकी साजिश रचने वाले और प्रायोजक अपनी करनी का फल अवश्य भुगतें। भारत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकियों या दबाव के आगे बिलकुल नहीं झुकेगा।

इसमें इस बात पर भी बल दिया गया है कि परमाणु हथियारों को डाल बनाकर आतंकवाद का बचाव करने के किसी भी प्रयास का सटीक और निर्णायक कार्रवाई से जवाब दिया जाएगा। आतंकवादियों को शरण देने, उन्हें धन देने या उनके लिए धन की व्यवस्था करने या आतंकवाद का समर्थन करने वालों को भी उनके समान ही परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीति का वास्तविक परीक्षण इसके क्रियान्वयन से ही होगा।

किसी भी नीति की सफलता व्यक्ति या संस्था विशेष पर ही निर्भर नहीं करती है। इसके लिए देश की सभी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस व अर्धसैनिक बलों इत्यादि के बीच उचित समन्वय, संसाधन के साथ-साथ तकनीकी क्षमता का विस्तार और दृढ़ इच्छा शक्ति भी नियमित बेहद जरूरी होगी। इसकी सफलता अब इसके प्रभावी कार्यान्वयन, आधुनिक तकनीक में निवेश और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर निर्भर करेगी। ऐसा होने के बाद ही 'प्रहार' सही मायने में देश को आतंकवाद से मुक्त कराने की दिशा में मजबूत और कारगर साबित होगा। भविष्य की दिशा 'प्रहार' राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सीमा-पार कार्रवाई को वैध बनाती है और वैश्विक मंचों पर सहयोग बढ़ाती है। यह पूर्व-सक्रिय रणनीति से भारत को मजबूत बनाएगी, लेकिन क्षमता निर्माण और कानूनी सुधार आवश्यक हैं।

सोशल फोरम

रटने की पीड़ाभरी परंपरा

आप कहती हैं कि आप गलत बोल रहे हैं.. 'मेरा बेटा खुद कोटा जा कर पढ़ना चाहता था, इसलिए मैं उसे कोटा ले कर गई पढ़ाने। मेरा बेटा खुद JEE क्लैक करना चाहता था। खूब पढ़ना चाहता था, मैंने दबाव नहीं डाला कभी।'



सिद्धांत थाकुर
ब्लॉगर

ये स्टेटमेंट आपका भ्रम हैं। आपकी अपनी लालसाएं हैं, जिन्हें आप अपने बच्चों पर थोप कर उन्हें अपना बताती हैं। आपका ये स्टेटमेंट बिलकुल वैसा ही है, जैसे मुस्लिम घरों में पैदा हुई लड़की कहती है कि 'हिजाब पहनना मेरी पसंद है। हिजाब मेरा प्राइड है और मुझे किसी ने कभी हिजाब या बुरा कहने के लिए दबाव नहीं बनाया।'... ऐसे ही आपका बेटा कोटा में पढ़ना चाहता है। बिलकुल ऐसे ही जैसे वो हिजाब पहनना चाहती है।

हिंदू घरों में पैदा हुई लड़कियां हिजाब क्यों नहीं पहनने को लालायित रहती हैं, क्या आपने कभी सोचा है? हिंदू लड़कियों के लिए हिजाब उनका गर्व या प्राइड क्यों नहीं बनता है क्या आपने सोचा है? ये सिर्फ रुढ़िवादी मुस्लिम परिवार में पैदा हुई लड़कियां ही क्यों कहती हैं? कोई भी बच्चा 25 साल तक किताबें रटना नहीं चाहता है। ये इतनी बड़ी पीड़ादायक परंपरा है, जो आप 'नशे' में रहते हुवे सोच भी नहीं सकते। कोई भी लड़का स्वयं से कभी कोटा जा कर 25 साल तक किताबें रटना नहीं चाहता। धर्म में तो फिर भी आशान है और लड़के वहां बगवती हो जाते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, पूजा नहीं करते हैं, मगर शिक्षा के मामले में आपने कभी आशान अपने बच्चों के आगे नहीं छोड़ा होता है।

यहां तक कि अगर आपका बेटा घर पर बैठकर ओपन स्कूल से स्टडी करना चाहे, जो कि सरकारी तौर पर उतना ही मान्य है। जितना रेगुलर बोर्ड, तो आप उसे वो भी आशान नहीं देते हैं। आपको इस तरह का नशा है, बच्चों को स्कूल भेजने का, कोटा भेजने का, कोचिंग में भेजने का कि आपके घरों में इसके आलावा कोई बात ही नहीं होती है। अब बारहवीं कर लिया तो अब आगे क्या, जाओ कोचिंग करो, ये एग्जाम निकालो, वो पास करो ये करो वो करो। बस!

कोटा, कोचिंग, स्कूल और कॉलेज आपके बनाए हैं। वयस्कों ने बनाया है। बच्चों ने नहीं बनाया है। आपने बच्चों के लिए पार्क में आठ घंटे खेलने का आशान बनाया होता, वो आठ घंटे खेलते। आपने उन्हें 'कोटा' का ही एक आशान दिया है। जीवन में तो वो बेचारे उसे न चुनें तो और क्या चुनेंगे?

-फेसबुक वॉल से

सामयिकी



कचरे पर न्यायपालिका के निर्देश और सच्चाई

सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के ठीक से पालन न होने पर चिंता जताई है और पहली अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए नियमों को प्रभावी बनाने के लिए कई निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि साफ और स्वस्थ पर्यावरण में जीना, जीवन के अधिकार का ही अहम हिस्सा है। यह मामला भोपाल नगर निगम की उन अपीलों से जुड़ा था, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर की गई थीं। अदालत ने कहा है कि अभी कानून में सुधार का इंतजार करना ठीक नहीं है, क्योंकि कचरे की खराब व्यवस्था से लोगों के स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था दोनों पर असर पड़ता है। कोर्ट ने माना कि पूरे देश में कचरा प्रबंधन नियमों का पालन समान रूप से नहीं हो रहा है और घरों से गीला-सूखा-खतरनाक कचरा अलग-अलग करने की व्यवस्था अभी तक भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। बड़े शहरों में बढ़ते कचरे के ढेर भी चिंता का कारण हैं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, 'अब नहीं तो कभी नहीं' और स्पष्ट किया कि अगर स्रोत पर कचरा अलग नहीं होगा और जरूरी सुविधाएं नहीं होंगी, तो अच्छे परिणाम की उम्मीद करना व्यर्थ है। अदालत ने पार्षदों, महापौरों और वार्ड प्रतिनिधियों को कचरा अलग कराने के लिए जिम्मेदार 'लीड फैसिलिटेटर' बनाने को कहा, ताकि हर नागरिक नियमों का पालन करे।

लीड फैसिलिटेटर वह व्यक्ति होता है जो किसी कार्यक्रम, प्रशिक्षण, कार्यशाला या परियोजना में पूरे समूह की प्रक्रिया का नेतृत्व करता है और यह सुनिश्चित करता है कि गतिविधियां सही दिशा में और निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार चलें। अच्छी बात यह है कि सभी नगर निकायों को 100% पालन के लिए समय-सीमा तय कर सार्वजनिक करने, प्रगति की फोटो जिलाधिकारी को भेजने और बड़े कचरा उत्पादकों से 31 मार्च तक नियमों का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को चार तरह के कचरे (गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष) के अलग-अलग प्रबंधन की व्यवस्था जल्दी तैयार करने को कहा गया है। अदालत ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया कि कचरा प्रबंधन नियमों को स्कूल की पढ़ाई में शामिल किया जाए। अब नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। पहले जुर्माना, बार-बार उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर आपराधिक केस भी दर्ज किया जा सकता है। लापरवाही करने वाले अधिकारी भी दायरे में आएंगे। कोर्ट ने मोबाइल अदालतों की संभावना पर भी विचार करने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली अप्रैल 2026 से देश के सभी न्यायालयों और संस्थानों में भी कचरा प्रबंधन नियमों का पालन होना चाहिए। नगर निकायों को लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाने होंगे, जैसे कचरा कम करना, घर में खाद बनाना और सैनिटरी कचरे को सुरक्षित तरीके से पैक करना। ये सभी निर्देश, इसलिए दिए गए हैं ताकि पहली अप्रैल 2026 से पहले पूरी तैयारी हो सके और नियम सही तरीके से लागू किए जा सकें।

कोर्ट ने सही चिंता जताई है कि ठोस कचरा प्रबंधन केवल पर्यावरण नहीं, बल्कि जन-स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। नियमों के कमजोर अनुपालन, स्थानीय निकायों की जवाबदेही की कमी और योजनाओं जैसे अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तथा स्मार्ट सिटीज मिशन में खामियों के कारण समस्या बढ़ी है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

आमने

लिखित उतर और मंत्री की तरफ से दिया गया जवाब अलग-अलग है। मंत्री बहुत सज्जन, सीधे हैं और बाइमेर के प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन बाइमेर जाते हैं, तो इन्हें काम नहीं करने दिया जाता। गृह क्षेत्र पाली में रहते हैं, तो वहां भी इन्हें काम नहीं करने दिया जाता।

-हरिश् चोधरी
-जोराराम कुमावत
कांग्रेस विधायक, राजस्थान

सामने

जिनके घर शीशे के बने होते हैं, वह दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। कांग्रेस की सरकार के समय जो दावे आए थे, उनमें से 21 के वक्रेम का निराकरण हमारी सरकार ने किया। आपकी तो पूरी योजना ही फेल हो गई। हम तो 42 लाख पशुओं को बीमा करेगे।

-जोराराम कुमावत
पशुपालन मंत्री, राजस्थान सरकार

कनिंघम ने नहीं, जगत सिंह ने खोजा था सारनाथ



निरंकार सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

विश्वविख्यात बौद्ध तीर्थस्थल सारनाथ की खोज के ऐतिहासिक तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि इसकी खोज वाराणसी के बाबू जगत सिंह ने की थी। बाद में इसकी खोज का श्रेय एलेक्जेंडर कनिंघम ने लिया। उन्होंने बाबू जगत सिंह की सूचनाओं को सही जानकारी भी नहीं दी, हालांकि बाबू जगत सिंह की सूचनाओं के आधार पर कनिंघम ने इसका उल्लेख कराया और वहां तमाम मूर्तियां भी मिलीं, जो आज सारनाथ संग्रहालय में रखी हुई हैं। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ऐतिहासिक तथ्यों को गहन छानबीन के बाद बाबू जगत सिंह के योगदान को स्वीकार कर लिया है।

अब तक इसकी खोज का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया जाता था। पर यह पूरा सच नहीं है, दरअसल इसकी खोज वाराणसी के बाबू जगत सिंह ने की थी। इस बौद्ध स्थल की खोज का इतिहास उल्लेखनीय और आकर्षक है। यह शानदार और अकल्पनीय रूप से विश्व के सामने आया। 1787 के आसपास एक विशिष्ट घटना घटी, जिसके पश्चात् इस स्थान ने विद्वानों, भिक्षुओं और पुरातत्वविदों का ध्यान आकर्षित करना आरंभ किया। लगभग 1787 में स्थानीय रासपरिवार के सदस्य और सारनाथ के जमींदार बाबू जगत सिंह को इस क्षेत्र में उपलब्ध इंटों और पत्थरों के अंबार का पता चला।

उन्होंने अपने नाम पर नगर में एक बाजार निर्मित करवाने के लिए इस निर्जन क्षेत्र को खोदकर यहां से आवश्यक निर्माण सामग्री प्राप्त करने का मन बनाया तथा मजदूरों को इस काम में लगा दिया गया। यह बाजार आज भी नगर में है और उन्हीं के नाम पर जगतगंज नाम से विख्यात है। धमेख स्तूप से पश्चिम में लगभग 520

फीट (158.5 मीटर) की दूरी पर इंटों और पत्थरों के ढेर को खोद निकाला गया। स्तूप के टोले से निर्माण सामग्री की खोदाई करते समय एक गोलक-रूप बलुआ पत्थर के बक्से के भीतर एक बेलनाकार हरे रंग की संगमरमर की मंजूषा मिली। बलुआ पत्थर का बक्सा और संगमरमरी मंजूषा सतह से अट्ठारह हाथ की गहराई पर पाए गए थे। संगमरमर के बक्से में मानव हड्डियां, क्षरित मोती, सोने की पत्तियां और अन्य मूल्यवान रत्न भी मिले थे। कालाविधि में अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया गया और दोनों बक्सों को कलकत्ता (कोलकाता) स्थित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को सौंप दिया गया। बक्सों और वस्तुओं के अतिरिक्त उसी स्थान पर भूमिगत बुद्ध की एक मूर्ति भी पाई गई थी, जिस मूर्ति के नीचे पाल राजा महिपाल का एक शिलालेख था।

यह विक्रम संवत् 1083 (ईस्वी सन् 1026) का दिनोक्त शिलालेख है, हालांकि 1835 में प्रकाशित कनिंघम की उत्खनन रिपोर्ट के साथ डंकन के आलेख को विश्लेषित करने पर एक अलग ही तस्वीर उभरती है। कनिंघम के अनुसार चुनार के बलुआ पत्थर का बक्सा स्तूप के अंदर 1835 में पाया गया था। उन्होंने इसे पास के गांव के एक व्यक्ति (संगकर या शंकर) द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर खोजा था, जो 1787 में स्तूप की खोदाई करने वाली टीम के मजदूरों में से एक था। उन्होंने बताया है कि बाबू जगत सिंह ने बलुआ पत्थर के बक्से को उसकी मूल स्थिति में ही छोड़ दिया था और मंजूषा के अंदर पाई गई हड्डियों को गंगा नदी में प्रवाहित करा दिया। गंगा नदी में अस्थि-विसर्जन हिंदू परंपराओं में दाह-संस्कार के बाद का महत्त्वपूर्ण संस्कार है। कनिंघम के

प्रसंगवश

अल्फ्रेड पार्क के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद

भारतीय इतिहास के आकाश में 27 फरवरी का दिन उस नक्षत्र की याद दिलाता है, जिसकी चमक से ब्रिटिश साम्राज्यवादी की आंखें चौंधिया गई थीं। यह दिन उस महामानव के बलिदान का साक्ष्य है, जिसने अपनी प्रतिज्ञा को अपने प्राणों से भी ऊंचा स्थान दिया। चंद्रशेखर आजाद, एक ऐसा नाम, जिसके स्मरण मात्र से धमनियों में रक्त का संचार तीव्र हो जाता है और हृदय में राष्ट्र भक्ति का ज्वार उमड़ पड़ता है। आजाद केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार थे, एक ऐसी जलती हुई मशाल थे, जिसने गुलामी के घोर अंधकार में करोड़ों भारतीयों को स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। उनका संपूर्ण जीवन एक ऐसी महागाथा है, जिसका प्रत्येक अध्याय साहस, त्याग और स्वाभिमान की स्याही से लिखा गया है।

मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में 23 जुलाई 1906 को जन्मे चंद्रशेखर सोनीराम तिवारी का बचपन अभावों की गोद में बीता। उनके पिता एक साधारण किसान थे, जो कड़ी मेहनत से परिवार का भरण-पोषण करते थे, लेकिन उस बालक की आंखों में नियति ने कुछ और ही स्वप्न सजो रखे थे। वे बचपन से ही निडर और साहसी थे, अन्याय को सहना उनके स्वभाव में नहीं था। जब 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की पुकार काशी की गलियों में गूंजी तो 14 वर्ष का यह बालक अपनी पढ़ाई छोड़कर राष्ट्र की वेदी पर आ खड़ा हुआ।

काशी की तंग गलियों में हाथ में तिरंगा लिए जब वह बालक अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध गर्जना कर रहा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटा सा किशोर आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देगा। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। उस कचहरी का दृश्य आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। मजिस्ट्रेट ने जब रोब से नाम पूछा तो बालक ने निर्भय होकर उत्तर दिया, 'आजाद'। पिता का नाम पूछने पर कहा, 'स्वतंत्रता' और निवास का पता बताया, 'जेलखाना'। मजिस्ट्रेट इस धृष्टता पर तिलमिला उठा और उसने 14 साल के उस कोमल शरीर को 15 कोड़ों की सजा सुनाई।

सरेआम उस बच्चे को निर्वस्त्र कर टिकटी से बांध दिया गया। भारी और मोटे बेंत का हर प्रहार उसकी खाल उधेक रहा था। पीट से खून के फव्वारे छूट रहे थे, लेकिन उन बालक की आंखों में दर्द नहीं, बल्कि एक अलौकिक गर्व था। हर कोड़े की मार पर वह पूरी ताकत से चिल्लाता था, 'वंदे मातरम!', 'भारत माता की जय!' 15 कोड़े पूरे होने तक उसका शरीर मांस का लोथड़ा बन चुका था, हड्डियां दिखाई देने लगी थीं, लेकिन उस वीर ने एक भी आंसू नहीं गिराया। जेल के डॉक्टर जब घावों पर दवा लगाते तो वह बच्चा दर्द से तड़पता जरूर था पर उसके होंठों पर मुस्कान और हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला थी। इसी दिन से वह दुनिया के लिए 'आजाद' बन गए।

असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने से आजाद का मोहभंग हुआ और वे सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ा गए। उनकी क्रांतिकारी यात्रा का एक स्वर्णिम पड़ाव 'काकोरी कांड' था। नो अप्रैल 1925 को लखनऊ के पास सरकारी खजाने से भरी ट्रेन को लूटकर क्रांतिकारियों ने फिरंगियों को सीधी चुनौती दी। इस कांड के बाद कई साथी पकड़े गए, लेकिन अपनी चतुराई और वेश बदलने की कला में माहिर आजाद पुलिस की आंखों में धूल झाँककर बच निकले। संगठन बिखर चुका था पर आजाद का हौसला नहीं। 1928 में उन्होंने बंगलूर सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे युवा मेधावियों के साथ मिलकर 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' की नींव रखी। आजाद इस संगठन के सेनापति थे। भगत सिंह जैसे प्रखर बुद्धिजीवी भी उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे।

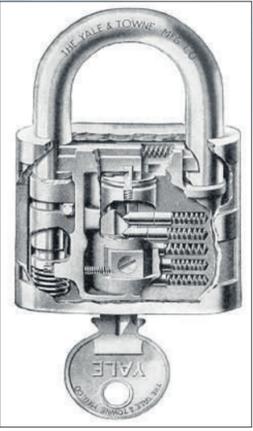
(ये लेखिका के निजी विचार हैं।)

ताले का आविष्कार

ताला मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन सुरक्षा साधनों में से एक है। माना जाता है कि ताले का प्रारंभ लगभग चार हजार वर्ष पूर्व हुआ। सबसे पुराने ताले प्राचीन मिस्र तथा मेसोपोटामिया में पाए गए हैं। ये ताले प्रायः लकड़ी के बने होते थे और कुंडी-खूंदी की विशेष व्यवस्था पर आधारित थे। जब चाबी भीतर डाली जाती थी, तो लकड़ी की खूंटियाँ ऊपर उठती थीं और द्वार खुल जाता था।

इसके पश्चात प्राचीन रोम में धातु के ताले और चाबियाँ बनने लगीं। रोमन शिल्पकारों ने लोहे और पीतल से छोटे, परंतु अधिक सुदृढ़ ताले बनाए। इससे सुरक्षा की व्यवस्था अधिक प्रभावी हुई। मध्यकाल में यूरोप में ताले केवल सुरक्षा का साधन ही नहीं रहे, बल्कि उन पर सुंदर नक्काशी और कलात्मक आकृतियाँ भी बनाई जाने लगीं।

आधुनिक ताले के विकास में उन्नीसवीं शताब्दी का विशेष योगदान रहा। सन् 1861 में अमेरिकी आविष्कारक लिनस येल जूनियर ने आधुनिक पिन-टंबलर सिलिंडर लॉक का पेटेंट कराया। यह प्रणाली आज भी व्यापक रूप से प्रचलित है और "येल लॉक" के नाम से जानी जाती है। इसने तालों को अधिक सुरक्षित, छोटा और उपयोग में सरल बना दिया। इस प्रकार ताले का आविष्कार किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों में विकसित हुई तकनीकों का परिणाम है। प्राचीन लकड़ी के साधारण ताले से लेकर आज के अंक-संकेत तथा अंगुली-छाप से खुलने वाले आधुनिक तालों तक, ताले ने मानव जीवन में सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।



वैज्ञानिक के बारे में

लिनस येल जूनियर का जन्म 4 जून 1821 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में हुआ था। उनके पिता लिनस येल सीनियर भी ताला निर्माण के क्षेत्र में कुशल कारीगर और आविष्कारक थे, जिससे उन्हें बचपन से ही इस कार्य का अनुभव मिला। येल जूनियर ने प्रारंभ में बैंक तिजोरियों की सुरक्षा प्रणाली पर काम किया, लेकिन बाद में छोटे और सुरक्षित सिलिंडर ताले के विकास में जुट गए। वे अत्यंत परिश्रमी और नवाचारप्रिय व्यक्ति थे। 1868 में उनका निधन हो गया, किंतु उनका आविष्कार आज भी विश्वभर में प्रचलित है।



कार्य का अनुभव

सूरे का

नदी की तलहटी में आधी गड़ी हुई या समुद्र के किनारे चट्टानों से चिपकी हुई सीपों में न तो कोई चमक-दमक होती है, न कोई तेज गति। वे न दिखावटी हैं, न ही हमारी रोजमर्रा की नजरों में आती हैं। फिर भी पूरी जलीय दुनिया बहुत हद तक इन्हीं खामोश जीवों पर टिकी हुई है। अगर सीपों को एक पंक्ति में समझना हो, तो कहा जा सकता है कि वे पानी की सफाईकर्मी हैं और ऐसे सफाईकर्मी, जो बिना थके, बिना रुके अपना काम करते रहते हैं।

एक सीप प्रतिदिन 20-40 लीटर छान सकती है पानी

सीप अपने शरीर में लगातार पानी खींचती हैं। इस पानी में मौजूद गंदगी, सूक्ष्म कण, बैक्टीरिया, शैवाल, रसायन और यहां तक कि भारी धातुओं को भी वे छान लेती हैं और अपेक्षाकृत साफ पानी वापस पर्यावरण में छोड़ देती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, सामान्य आकार की एक सीप प्रतिदिन 20 से 40 लीटर तक पानी छान सकती है। अब कल्पना कीजिए, यदि किसी नदी, झील या समुद्री तट पर हजारों या लाखों सीपों हो, तो वे कितनी विशाल मात्रा में पानी को स्वाभाविक रूप से साफ रखती होंगी। दुनियाभर में सीपों की 1200 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 1000 प्रजातियाँ मीठे पानी में और शेष समुद्री जल में निवास करती हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि मीठे पानी की सीपों की सबसे अधिक विविधता उत्तरी अमेरिका में मिलती है, जहाँ अकेले लगभग 300 प्रजातियाँ मौजूद हैं। यूरोप में करीब 16 प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जबकि एशिया में भी मीठे पानी और समुद्री, दोनों तरह की सीपों की संख्या काफी अधिक है। चीन, भारत, जापान और दक्षिण-पूर्व एशिया के देश सीपों की जैव विविधता और खेती दोनों के लिए जाने जाते हैं।



कुमार सिद्धार्थ
बहिर पत्रकार

जीवन चक्र और मोती बनने की प्रक्रिया

सीपों की बनावट देखने में सरल, लेकिन कार्य में अत्यंत प्रभावशाली होती है। दो मजबूत खोलों के भीतर उनका कोमल शरीर सुरक्षित रहता है। ये खोल कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, जिसे सीपें पानी से धीरे-धीरे लेकर परत-दर-परत जमा करती रहती हैं। यही कारण है कि उनका खोल जीवनभर बढ़ता रहता है। मोती बनने की प्रक्रिया भी इसी से जुड़ी है। जब कोई बाहरी कण सीप के शरीर के भीतर फंस जाता है, तो वह उसे ढकने के लिए कैल्शियम की परतें बढ़ती जाती हैं और समय के साथ वही कण मोती का रूप ले लेता है। सीपों का जीवन चक्र भी कम रोचक नहीं है। समुद्री सीपें अपने अंडे और श्रुण्णु पानी में छोड़ती हैं, जिनसे सूक्ष्म लार्वा बनते हैं। ये लार्वा कुछ समय तक समुद्र में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं और फिर किसी ठोस सतह चढ़न, खोल या तट से चिपककर स्थायी जीवन शुरू करते हैं। मीठे पानी की कई सीपें इससे भी अनोखा तरीका अपनाती हैं। उनके लार्वा कुछ समय तक मछलियों के गलफड़ों या पंखों से चिपककर रहते हैं और फिर किसी ठोस सतह चढ़न, खोल या तट से चिपककर स्थायी जीवन शुरू करते हैं। यदि मछलियाँ कम हों, तो सीपों का भविष्य भी संकट में पड़ जाता है। सीपों की एक और विशेषता उनकी लंबी उम्र है। समुद्री सीपें आमतौर पर 10 से 20 वर्ष तक जीवित रहती हैं, जबकि मीठे पानी की कई प्रजातियाँ 50 से 100 वर्ष तक भी जी सकती हैं।

सीप की खेती

एशिया में सीपों की खेती समुद्र और इंसान के पुराने रिश्ते का विस्तार है। चीन, जापान, थाईलैंड और वियतनाम में सीपों को "उगाया" नहीं जाता, बल्कि उन्हें ऐसा वातावरण दिया जाता है, जहां वे स्वाभाविक रूप से पनप सकें। समुद्र के किनारे बांस, रस्सियों और टाइलों पर लार्वा चिपक जाते हैं और फिर समुद्र अपना काम करता है। चीन इस क्षेत्र में सबसे आगे है। दुनिया में उत्पादित समुद्री सीपों का बड़ा हिस्सा वहीं से आता है। यह खेती लाखों लोगों को रोजगार देती है—मछुआरों से लेकर रेस्तरां और निर्यात तक। सीपों का उपयोग केवल भोजन तक सीमित नहीं है। उनके खोलों से बुना, खाद और निर्माण सामग्री बनती है। भोजन के रूप में वे प्रोटीन, जिंक, आयरन और ओमेगा-3 से भरपूर होती हैं। अगर सीपें कम होती गईं, तो पानी की गुणवत्ता गिरेगी, शैवाल विस्फोट बढ़ेंगे, मछलियाँ मरेगी और तटीय समुदायों की आजीविका संकट में पड़ जाएगी।



सीपों के लिए चुनौती बनता समुद्र का अम्लीयकरण

पिछले कुछ दशकों में स्थिति चिंताजनक होती गई है। मीठे पानी की लगभग एक हजार प्रजातियों में से अधिकांश या तो संकटग्रस्त हैं या तेजी से घट रही हैं। पोलैंड, क्रोएशिया और ब्रिटेन जैसे देशों में बड़े पैमाने पर सीपों की मृत्यु दर्ज की गई है। लंदन की टेम्स नदी में पिछले 60 वर्षों में मीठे पानी की लगभग सारी सीपें समाप्त हो चुकी हैं। उत्तरी अमेरिका में 70 प्रतिशत से अधिक मीठे पानी की सीपें प्रजातियाँ संकटग्रस्त या विलुप्ति की कगार पर हैं। इन संकटों के पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। पानी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्रीष्म लहरें तीव्र हो रही हैं। जब नदी या समुद्र का पानी अचानक बहुत गर्म हो जाता है, तो सीपें उसे सहन नहीं कर पाती और बड़े पैमाने पर मर जाती हैं। इसके साथ ही रासायनिक प्रदूषण, माइक्रोप्लास्टिक, नदियों का प्राकृतिक बहाव बदलना, बांध, खनन और शहरी सीवेज इस संकट को और गहरा कर रहे हैं। महासागरों में समुद्र का अम्लीयकरण भी बड़ी चुनौती बन चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड के घुलने से पानी अम्लीय हो रहा है, जिससे सीपों के खोल बनने की प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। शिशु सीपें तो कई बार खोल बना ही नहीं पाती।

समुद्र के छुपे हुए सफाईकर्मी

समुद्री सीपें तटीय इलाकों के लिए जीवन-रेखा जैसी हैं। वे पानी साफ रखती हैं, तटों को कटाव से बचाती हैं, छोटी मछलियों और केकड़ों को आश्रय देती हैं और मत्स्य उत्पादन को स्थिर बनाए रखती हैं। जहां सीपों की चट्टानें होती हैं, वहां जैव विविधता कई गुना बढ़ जाती है। एशियाई देशों विशेषकर अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में सीपों की गिरावट का असर प्रवाल भित्तियों और मछली जीवन पर साफ दिखने लगा है। बढ़ता तापमान, पर्यटन से फैला कचरा, प्लास्टिक और तटीय विकास इन नाजुक तंत्रों को कमजोर कर रहे हैं। फिर भी उम्मीद बाकी है। वॉशिंगटन डीसी की पनाकोस्टिया नदी में सीपों की मदद से पानी साफ किया जा रहा है। यह दिखाता है कि अगर हम पानी को साफ करें, तो सीपें लौट सकती हैं। सीपों में अनुकूलन की अद्भुत क्षमता होती है। हर सामूहिक मृत्यु के बाद कुछ सीपें बचती हैं और वहीं नई पीढ़ी की नींव बनती हैं। यही उम्मीद है। इन खामोश सफाईकर्मीयों को बचाना, दरअसल अपने जल, अपने पर्यावरण और अपने भविष्य को बचाना है।

मरीन लाइफ

समुद्र की अथाह गहराइयों में एक ऐसा जीव भी रहता है, जिसे देखकर पहली नजर में विश्वास ही नहीं होता कि यह मछली है। समुद्री सनफिश या मोलामोला, दुनिया की सबसे भारी अस्थि-मछली मानी जाती है। इसका गोल, पाश्र्व रूप से चपटा शरीर और विशाल पंख इसे समुद्री दुनिया का अनोखा आकर्षण बनाते हैं। वयस्क सनफिश का वजन 2,000 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है और इसकी लंबाई 10 फीट तक पहुंच सकती है। इतनी विशाल काया के बावजूद इसका पसंदीदा भोजन है—जेलीफिश। जेलीफिश लगभग पूरी तरह पानी से बनी होती है और उनमें पोषक तत्व बेहद कम होते हैं। इसलिए सनफिश को अपनी



ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में जेलीफिश निगलनी पड़ती है। यही कारण है कि वे लगातार भोजन की तलाश में लंबी दूरी तय करती

हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये मछलियाँ हजारों किलोमीटर की समुद्री यात्रा कर सकती हैं और 600 मीटर से अधिक गहराई तक गोता लगा सकती हैं। इनकी वृद्धि दर आश्चर्यजनक है। नवजात सनफिश का वजन एक ग्राम से भी कम होता है, लेकिन वयस्क होने पर यह अपने जन्म वजन से लगभग 6 करोड़ गुना बड़ी हो सकती है। यह आकार परिवर्तन जीव जगत में सबसे चौंकाने वाले विकासों में से एक है। हालांकि वयस्क सनफिश का आकार उन्हें अधिकांश शिकारियों से सुरक्षित रखता है, फिर भी मध्यम आकार की सनफिश समुद्री शेर, किलर व्हेल और बड़ी शाक का शिकार बन जाती हैं। कैलिफोर्निया के समुद्री शेरों द्वारा छोटी सनफिश

के पंख काटकर उन्हें खेल की वस्तु की तरह उछालना समुद्री व्यवहार का एक विचित्र उदाहरण है। प्रजनन के विषय में अभी भी कई रहस्य बने हुए हैं। मादा सनफिश एक बार में 3 से 30 करोड़ तक अंडे दे सकती है, जो किसी भी अन्य कशेरुकी जीव से अधिक है। नर उसी समय पानी में श्रुण्णु छोड़ते हैं, जिससे निषेचन की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि वैज्ञानिक अब भी यह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि वे समूह में प्रजनन करती हैं या जोड़े में। समुद्री सनफिश न केवल आकार में विशाल है, बल्कि अपने रहस्यों और अद्भुत जीवनशैली के कारण समुद्री जगत की सबसे रोचक प्रजातियों में से एक है।

समुद्र की सतह पर धूप सेंकती रहस्यमयी मछली

उड़न तश्तरियों का रहस्य

प्राचीन सभ्यताओं में संकेत

दिलचस्प बात यह है कि उड़न तश्तरियों के प्रमाण केवल आधुनिक युग तक सीमित नहीं हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथों में 'विमानों' का वर्णन मिलता है, जो हवा में अविश्वसनीय गति से उड़ सकते थे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की गुफाओं में मिले 10,000 साल पुराने शैलचित्रों में ऐसी आकृतियाँ देखी गई हैं, जो आधुनिक अंतरिक्ष यानों और तश्तरीनुमा यानों जैसी दिखती हैं। इसी तरह प्राचीन मिस्र, सुमेरियन और माया सभ्यताओं की कलाकृतियों में भी 'आकाश से आए देवताओं' और उनके उड़ने वाले रथों का उल्लेख मिलता है, जिसे आज के 'प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतवादी' (Ancient Alien Theorists) एलियंस के आगमन से जोड़कर देखते हैं।

रहस्य या रणनीति

दशकों तक UFO को केवल लोगों का भ्रम या कल्पना माना गया, लेकिन 2017 के बाद परिदृश्य बदल गया। अमेरिकी रक्षा विभाग (पेटागन) ने आधिकारिक तौर पर तीन वीडियो जारी किए, जिन्हें नौसेना के पायलटों ने रिकॉर्ड किया था। इन वीडियो में 'टिक-टैक' (Tic-Tac) आकार की वस्तुएं भौतिकी के नियमों को धता बताते हुए समुद्र के ऊपर उड़ती दिखीं। सरकारें अब इसे 'एलियंस' के बजाय 'राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे' के रूप में देख रही हैं। चिंता इस बात की है कि क्या चीन या रूस जैसे प्रतिस्पर्धी देशों ने ऐसी कोई 'हाइपरसोनिक' तकनीक विकसित कर ली है, जो अमेरिकी रडार को चकमा दे सके। इसी कारण से अमेरिकी ने 'AARO' नामक विभाग बनाया है, जो इन घटनाओं की वैज्ञानिक जांच करता है।

भौतिक विज्ञान की चुनौतियाँ

UFO की सबसे रहस्यमयी बात उनकी गतिशीलता है। चरमदीयों और रडार डेटा के अनुसार, ये वस्तुएं अचानक स्थिर अवस्था से हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती हैं। वे बिना किसी पंख (wings) या स्पष्ट प्रोपल्शन इंजन के उड़ती हैं और 'सोनिक बूम' पैदा किए बिना ध्वनि की गति को पार कर जाती हैं। भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार, इतनी तीव्र गति से दिशा बदलने पर किसी भी मानव शरीर या पारंपरिक विमान के परखच्चे उड़ सकते हैं। यह संकेत देता है कि यदि ये यान वास्तविक हैं, तो इनके पास 'गुरुत्वाकर्षण-विरोधी' (Anti-gravity) तकनीक है, जो वर्तमान मानव विज्ञान की समझ से बहुत आगे है।

मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रभाव

उड़न तश्तरियों के रहस्य का एक पहलू सामूहिक मनोविज्ञान भी है। शीत युद्ध के दौरान, आसमान में उड़ने वाली अज्ञात वस्तुओं का डर अक्सर जासूसी विमानों का होता था। वहीं, हॉलीवुड फिल्मों (जैसे E.T., Independence Day) ने हमारे मन में एलियंस की एक खास छवि गढ़ दी है। कई बार लोग तारों, ग्रहों (विशेषकर शुक्रे), उपग्रहों (जैसे एलन मस्क की स्टारलिनक स्पेसलाइट) या पक्षियों के झुंड को गलती से UFO समझ लेते हैं। उड़न तश्तरियों का रहस्य आज भी अनसुलझा है, हालांकि अब तक कोई ऐसा ठोस प्रमाण सार्वजनिक नहीं हुआ है, जो यह साबित कर सके कि ये यान किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, लेकिन हजारों की संख्या में विश्वसनीय गवाह (पायलट, वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी) इस बात की पुष्टि करते हैं कि आसमान में कुछ ऐसा है, जो हमारी समझ से परे है। ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए, जहां अरबों आकाशगंगों और अनगिनत पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, यह मानना तर्कसंगत लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। शायद उड़नतश्तरियों केवल यान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के उभरते सत्य का द्वार है, जिससे हमारा सम्मान होना अभी बाकी है।

वैज्ञानिक फैक्ट



जीवन से भरपूर है मिट्टी

हम अक्सर मिट्टी को केवल धूल या जमीन का एक साधारण हिस्सा समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में मिट्टी जीवन का विशाल और अद्भुत संसार अपने भीतर समेटे हुए है। वैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टी के केवल एक चम्मच में जितने सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, उनकी संख्या पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों से भी अधिक हो सकती है। यह तथ्य अपने आप में बताता है कि मिट्टी कितनी जीवंत और महत्वपूर्ण है।

अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार मिट्टी में लाखों प्रजातियाँ और अरबों जीव पाए जाते हैं। इनमें बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, सूक्ष्म कीट, केंचुए, भृंग, चींटियाँ, घुन और कई अन्य जीव शामिल हैं। ये सभी मिलकर पृथ्वी पर कहीं भी पाए जाने वाले जैव द्रव्यमान का सबसे बड़ा संकेन्द्रण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मिट्टी पृथ्वी का सबसे व्यस्त और सक्रिय पारिस्थितिक तंत्र है।

मिट्टी के ये सूक्ष्मजीव केवल संस्था में अधिक नहीं होते, बल्कि अत्यंत उपयोगी भी होते हैं। बैक्टीरिया और कवक मृत पौधों और जीवों को विघटित करके उन्हें पोषक तत्वों में बदलते हैं। यही पोषक तत्व फसलों और पेड़ों की जड़ों तक पहुंचते हैं और उन्हें स्वस्थ विकास में मदद करते हैं। केंचुए मिट्टी को भुरभुरी बनाकर उसमें हवा और पानी के प्रवाह को बेहतर करते हैं, जिससे पौधों की जड़ें आसानी से फैल सकें।

स्वस्थ मिट्टी केवल कृषि के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिट्टी कार्बन को अपने भीतर संग्रहित करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करती है। साथ ही, यह वर्षा के पानी को सोखकर भूजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होती है। यदि मिट्टी की गुणवत्ता घटती है, तो इसका सीधा असर खाद्य उत्पादन, जल संसाधनों और जैव विविधता पर पड़ता है।

आज रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग, प्रदूषण और अंधाधुंध निर्माण के कारण मिट्टी की सेहत प्रभावित हो रही है। इसलिए जरूरी है कि हम जैविक खेती, वृक्षारोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान दें। मिट्टी को बचाना दरअसल जीवन को बचाना है, क्योंकि यही धरती का वह आधार है, जिस पर हमारा पूरा अस्तित्व टिका हुआ है।



क्या अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों में हम अकेले हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है कि इस सवाल ने सदियों से इंसानों को परेशान रखा है। इसके पक्ष-विपक्ष में सैकड़ों तर्क-वितर्क दिए जाते हैं। जब भी आकाश में कोई अज्ञात चमकती हुई वस्तु या अजीब आकार का यान दिखाई देता है, तो उसे 'उड़न तश्तरी' या UFO (Unidentified Flying Object) का नाम दे दिया जाता है। आधुनिक समय में, वैज्ञानिक इसे UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) कहते हैं। उड़न तश्तरियों का रहस्य केवल कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि यह विज्ञान, राष्ट्रीय सुरक्षा और दर्शन का एक जटिल मिश्रण बन चुका है।
-फिचर डेस्क

बाजार	संसेक्स ↓	निफ्टी ↑
बंद हुआ	82,248.61	25,496.55
गिरा/बढ़त	27.46	14.05
प्रतिशत में	0.03	0.06

सोना 1.62 लाख प्रति 10 ग्राम

चांदी 2,70,500 प्रति किलो

अमृत विचार

लखनऊ, शुक्रवार, 27 फरवरी 2026

www.amritvichar.com

कारोबार

बिजिनेस ब्रीफ

फूड ऐप 'टोइंग' का एनसीआर में प्रवेश

नई दिल्ली, एजेंसी। फिफायटी फूड डिलिवरी ऐप टोइंग ने दिल्ली-एनसीआर में विस्तार की घोषणा की है। कंपनी ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञापित में बताया कि अब टोइंग दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध होगा। यह पुणे, आगरा, वडोदरा, गुवाहाटी, नासिक और नागपुर में पहले से उपलब्ध है। कंपनी अपने ऐप पर खाद्य पदार्थों की सबसे कम कीमतों को दावा करती है। इसके अलावा, किसी भी ऑर्डर पर कोई पैकेजिंग शुल्क या प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लेती है।

इनविट निवेशकों को तिमाही में मिला 5,565 करोड़ का 'रिटर्न'

नयी दिल्ली, एजेंसी। बाजार में सूचीबद्ध अवसरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में करीब चार लाख यूनिटधारकों को कुल 5,565 करोड़ रुपये का 'रिटर्न' वितरित किया है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में यूनिटधारकों को 4,287 करोड़ रुपये का रिटर्न या प्रतिफल मिला था। भारत इनविट संघ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एन. एस. वेकटेश ने कहा, इनविट परिवेश तंत्र विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसमें घरेलू एवं वैश्विक निवेशकों की भागीदारी बढ़ रही है।

बंधन बैंक में बड़ी हिस्सेदारी खरीदेगा एसबीआई

कोलकाता, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एसबीआई म्यूचुअल फंड के बंधन बैंक में 9.99 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बंधन बैंक ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजारों को दी सूचना में बताया कि आरबीआई ने 25 फरवरी, 2026 के पत्र के माध्यम से एसबीआई म्यूचुअल फंड को बैंक की चुकता शेयर पूंजी या मतदान अधिकारों में अधिकतम 9.99 प्रतिशत तक हिस्सेदारी अधिग्रहीत करने की अनुमति प्रदान की है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आवेदक पत्र की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रस्तावित प्रमुख हिस्सेदारी हासिल नहीं करता है, तो मंजूरी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। साथ ही एसबीआई म्यूचुअल फंड की कुल हिस्सेदारी किसी भी समय बैंक की चुकता शेयर पूंजी या मतदान अधिकारों के 9.99 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

डब्ल्यूटीओ में भारत की व्यापार नीति की समीक्षा जुलाई में होगी

नयी दिल्ली, एजेंसी। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत की आठवीं व्यापार नीति समीक्षा इस साल जुलाई में होगी। इस दौरान सदस्य देशों की तरफ से भारत की व्यापार नीतियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। वित्त मंत्रालय ने कहा कि व्यापार नीतियों की इस समीक्षा से पहले भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने डब्ल्यूटीओ में भारत के डिजिटल कस्टम सुधारों और व्यापार सुगमता समझौते के क्रियान्वयन को प्रस्तुत किया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीबीआईसी की सदस्य (सीमा शुल्क) सुजीत भुजबल ने किया।

20 लाख तक की प्रॉपर्टी पर पैस से मिल सकती है राहत

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

अमृत विचार। छोटा घर या 20 लाख रुपये तक की जमीन खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। आयकर विभाग द्वारा प्रस्तावित नए आयकर नियमों के ड्राफ्ट में प्रॉपर्टी लेनदेन से जुड़े पैस अनिवार्यता नियमों में बदलाव का सुझाव दिया गया है। यह प्रस्ताव लागू होता है, तो कम कीमत की संपत्ति के खरीदारों को बड़ी सहूलियत मिल सकती है। वर्तमान में 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति जैसे मकान, प्लॉट या फ्लैट आदि की खरीद-फरोख्त में पैस देना अनिवार्य है। नए प्रस्ताव में इस सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की बात कही गई है। यानी 20 लाख रुपये से कम मूल्य की रजिस्ट्री में पैस देना जरूरी नहीं रहेगा।

विकसित यूपी का संकल्प



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागाशाकी से भेट कर विकास और निवेश के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। नागाशाकी ने आगामी अगस्त माह में 200 जापानी सीईओ के साथ उत्तर प्रदेश आने का प्रस्ताव दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने उम्माक स्वागत किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और यामानाशी प्रांत के बीच उद्योग, पर्यटन और ग्रीन हाइड्रोजन समेत अनेक क्षेत्रों में सहयोग के एमओयू साइन हुए।

सोशल मीडिया पोस्ट के साथ नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर का उल्लेख जरूरी

सोशल मीडिया पर शेयर मार्केट सम्बंधी सामग्री डालने पर सेबी के निर्देश, एक मई से होंगे लागू

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को अपने नियमन दायरे में आने वाली सभी इकाइयों और उनके एजेंट को निर्देश दिया कि वे सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिभूति बाजार से संबंधित सामग्री डालते समय अपना पंजीकृत नाम और पंजीकरण संख्या का उल्लेख करें। सेबी का यह निर्देश शेयर ब्रोकर, म्यूचुअल फंड कंपनियों, संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमएसी), निवेश सलाहकार, शोध विश्लेषक, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), पोर्टफोलियो प्रबंधकों और अन्य पर लागू होगा। सेबी ने अपने परिपत्र में कहा, "सोशल मीडिया के इस्तेमाल और स्वीकार्यता में तेजी से बढ़ोतरी होने के साथ इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि नियमन के दायरे में आने वाली इकाइयों को



- होमपेज पर सभी पंजीकरण की सूची वाला एक वेब लिंक देना होगा
- एजेंट को प्रत्येक पोस्ट में पंजीकरण ब्योरा देना अनिवार्य

सोशल मीडिया पर प्रतिभूति बाजार से संबंधित सामग्री डालते समय अपना पंजीकरण संख्या और नाम बताया जाना चाहिए।" ये नियम एक मई 2026 से लागू हो जाएंगे।

बाजार नियामक ने कहा कि इसके अलावा, एजेंट को अपने पंजीकरण ब्योरे के साथ प्रमुख इकाई के पंजीकरण ब्योरे की भी जानकारी देनी होगी। इन नए नियमों का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशकों का संरक्षण करना है। ये नियम एक मई, 2026 से प्रभावी होंगे।

बंद होंगे रिटायरमेंट और चिल्ड्रेन फंड्स

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

अमृत विचार। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड उद्योग में बड़ा संरचनात्मक बदलाव करते हुए स्कीमों के कैटेगरीजेशन और रेशनलाइजेशन का नया ढांचा लागू करते हुए 'सॉल्यूशन ओरिएटेड स्कीम' कैटेगरी समाप्त कर दी है। इसमें मुख्य रूप से रिटायरमेंट और चिल्ड्रेन फंड शामिल थे। अब इन स्कीमों को समान एसेट एलोकेशन और जोखिम प्रोफाइल वाली अन्य श्रेणियों में विलय किया जाएगा। इसके लिए सेबी ने 'लाइफ साइकिल फंड' नामक नई श्रेणी बनाई है, जिसे अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी माना जा रहा है। इस बदलाव का उद्देश्य निवेशकों को भ्रम से बचाना, स्कीमों के नाम और निवेश रणनीति में एकरूपता लाना है।

स्कीमों के नाम में रिटर्न या भावनात्मक शब्दों पर रोक

सेबी "टू टू लेवल" सिद्धांत सखी से लागू कर रहा है। इसका अर्थ है कि स्कीम का नाम, उसका निवेश उद्देश्य, एसेट एलोकेशन और वास्तविक पोर्टफोलियो सभी एक-दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हों। लेकिन सॉल्यूशन ओरिएटेड स्कीमों इस कसौटी पर खरी नहीं उतर रही थीं। नाम लक्ष्य आधारित, पर निवेश रणनीति व्यापक और कई बार अस्पष्ट होता था। नए ढांचे में सेबी ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कीमों के नाम में रिटर्न या भावनात्मक शब्दों के प्रयोग पर रोक रहेगी और श्रेणी के हिसाब से नामकरण होगा।

'लाइफ साइकिल फंड' वैज्ञानिक मॉडल

- 5 से 30 वर्ष की पूर्व निर्धारित अवधि
- लक्ष्य वर्ष जैसे 2045, 2055 के साथ स्कीम का नाम
- परिपक्वता नजदीक आने पर इक्विटी घटेंगी और डेट बढ़ेगी
- गोल्ड/सिल्वर ईटीएफ व अन्य एसेट क्लास में सीमित निवेश

भ्रम हटेगा, समझ बढ़ेगी

वित्तीय सलाहकार राजीव सिंह का कहना है कि मौजूदा निवेशकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनकी स्कीमों सीधे बंद नहीं होंगी, बल्कि समान संरचना वाली श्रेणी में समाहित की जाएगी। हालांकि, निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा अवश्य करनी चाहिए। सॉल्यूशन ओरिएटेड स्कीमों का बंद होना केवल एक श्रेणी का अंत नहीं, बल्कि म्यूचुअल फंड उद्योग के परिपक्व होने का संकेत है। लक्ष्य आधारित निवेश की अवधारणा खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसे और अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी रूप में प्रस्तुत किया गया है। लंबी अवधि में यह कदम निवेशकों को बेहतर समझ, कम भ्रम और अधिक पारदर्शिता प्रदान करेगा। नियामकीय दृष्टि से यह सुधार उत्पादों की संख्या से अधिक गुणवत्ता पर जोर देने वाला है।

सैमसंग के सस्ते स्मार्टफोन भी होंगे एआई से लैस

जानकारी

नो कॉस्ट EMI क्या एक स्कैम है! जानिए बारीकियां

कारोबार डेस्क

तकनीकी रूप से यह कोई कानूनी "स्कैम" या धोखाधड़ी नहीं है, लेकिन यह मार्केटिंग का एक ऐसा खेल है जिसमें असली कीमत बारीक अक्षरों (फाइन प्रिंट) में छिपी होती है। यहाँ बताया गया है कि यह "नो कॉस्ट" का जादू असल में कैसे काम करता है:

"नो कॉस्ट" असल में आपको कैसे महंगा पड़ता है : बैंक और कंपनियों कभी भी मुफ्त में पैसा उधार नहीं देती। आरबीआई के नियमों के अनुसार, बैंक ब्याज लेंगे ही, लेकिन उसे छिपाने के दो मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं: **छिपे हुए खतरे और नुकसान** : ब्याज पर जीएसटी: भले ही मर्चेट ने आपको ब्याज पर छूट दे दी हो, लेकिन बैंक जो ब्याज लगाता है, उस पर आपको 18% जीएसटी अलग से देना पड़ता है। यह आपको जेब से एक्स्ट्रा जता है। **क्रेडिट स्कोर पर असर**: हर ईएमआई एक तरह का लोन है। एक साथ कई ईएमआई चलाने से आपके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ सकता है। **फिजुअल चार्ज**: 50,000 की चीज जब 4,000 महीने पर दिखने लगती है, तो हम वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। इसे ही "डेब्ट ट्रेप" कहते हैं।

यूपी को 'डीप टेक कैपिटल' बनाएगा आईआईटी

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

अमृत विचार। प्रदेश को डीप टेक स्टार्टअप का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में आईआईटी कानपुर लगातार जिस तरह बड़े कदम उठा रहा है, उससे टैलेंट, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की बुनियाद पर देश में यूपी 'डीप टेक कैपिटल' बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है।

डीप टेक इनोवेशन को मजबूत करने के लिए गुरुवार को एचसीएल टेक और आईआईटी के बीच हुई साझेदारी ने इसी बात को साबित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही आईआईटी में हुए देश के पहले डीपटेक सम्मेलन में आईआईटी कानपुर को डीप टेक इनोवेशन का प्रमुख केंद्र बनाने की

- एचसीएल टेक और आईआईटी मिलकर आगे बढ़ाएंगे डीप टेक इनोवेशन

घोषणा कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने भी इसी माह डीपटेक स्टार्टअप के लिए टर्नओवर सीमा बढ़ाकर 300 करोड़ की है।

वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी एचसीएल टेक और आईआईटी कानपुर ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान को वास्तविक पायलट प्रोजेक्ट्स और स्कैलेबल समाधानों में बदलने के लिए गुरुवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए उन्नत तकनीकी समाधान विकसित करना

- एआई, रोबोटिक्स पर अनुसंधान आधारित नवाचार पूरी करेगा उद्योगों की वास्तविक जरूरत

और रिसर्च को इंडस्ट्री से जोड़ना है। यह साझेदारी उन्नत अभियांत्रिकी और डीप टेक के क्षेत्रों में, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान देते हुए, अनुसंधान-आधारित नवाचार को सक्षम बनाने के लिए एचसीएल टेक को विश्वसनीय ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भागीदार के रूप में स्थापित करेगी। इस पहल के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ऑटोमेशन और अन्य उभरती तकनीकों पर संयुक्त शोध किया

जाएगा। मकसद नई तकनीकों को प्रयोगशाला से निकालकर उद्योग की वास्तविक जरूरतों के अनुसार तैयार करना होगा। एचसीएलटेक की इंडस्ट्री विशेषज्ञता और आईआईटी की अकादमिक क्षमता मिलकर ऐसे समाधान विकसित करेंगे जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होंगे। इस साझेदारी युवाओं और छात्रों को स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री एक्सपोजर के नए अवसर मिलेंगे। इससे भविष्य के टेक लीडर्स तैयार होंगे। यह साझेदारी देश के डीप टेक इकोसिस्टम को गति देने, रिसर्च को व्यावहारिक समाधान में बदलने और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

सोने की चमक कायम रहने की उम्मीद : रिपोर्ट

मुंबई, एजेंसी

वैश्विक स्तर पर डॉलर के प्रभाव में कमी, राजकोषीय दबाव और बढ़ते वैश्विक तनावों के कारण दुनिया में वित्तीय व्यवस्था में हो रहे बदलावों को देखते हुए सोने का दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है और इसमें तेजी बने रहने की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (एमओएफएसएल) ने सोने पर अपनी तिमाही रिपोर्ट में कहा कि 2026 की शुरुआत में सोने की कीमत 5,000 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गई। यह आधुनिक इतिहास में सबसे मजबूत दीर्घकालिक तेजी के दौर में से एक है।

रिपोर्ट के अनुसार, सोना 'संरचनात्मक रूप से पुनर्मूल्यांकन चरण' में प्रवेश कर चुका है। यह चक्रव्युत्तेजी के बजाय एक नए 'सुपरसाइकल' की शुरुआत का संकेत है। एमओएफएसएल को उम्मीद है कि अगले 12 महीनों में कॉमेक्स सोने की कीमत 6,000 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस (घरेलू बाजार में 1.85 लाख रुपये प्रति



10 ग्राम) के आसपास स्थिर होगी। यदि वैश्विक स्तर पर तनाव और राजकोषीय उपाय तेज होते हैं तो मध्यम अवधि में यह 7,500 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस तक भी पहुंच सकती है।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के जिन शोध मामलों के प्रमुख नवनीत दमानी ने कहा, 'सोने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सीमित खदान उत्पादन, प्रमुख बाजारों में घटते भंडार और बढ़ती उत्पादन लागत के कारण वैश्विक भौतिक आपूर्ति में कमी ने भी कीमती धातुओं की कीमतों को उच्चस्तर पर बनाया रखा है। घरेलू बाजार में, रुपये के मूल्य में गिरावट और खुदरा खरीदारों की मजबूत लिवाली से मांग में वृद्धि हुई है।

सोशल मीडिया पर प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को लेकर डाली जा रही है गलत जानकारी : पासवान

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग मंत्री विराग पासवान ने बृहस्पतिवार को कहा कि सोशल मीडिया पर असर करने वाले लोग 'गलत बात' फैला रहे हैं कि प्रसंस्कृत खाद्य नुकसानदायक हैं। उन्होंने सोशल मीडिया 'इन्फ्लूएंसर' द्वारा फैलाई जा रही इस तरह की गलत धारणा का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई और साथ ही चेतावनी दी कि इससे क्षेत्र के विकास में बाधा आ सकती है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्योगिता एवं प्रबंधन संस्थान-कुंडली (निपेट-के) द्वारा आयोजित तीन दिनों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'अनवेध-2026' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पासवान ने कहा कि यह सोच कि प्रसंस्कृत खाद्य का मालब अस्वस्थ नहीं है को ऑनलाइन पर सक्रियता से प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम न केवल अपने देश में, बल्कि

वैश्विक स्तर पर भी इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, इससे इस क्षेत्र पर असर पड़ रहा है और यह और बढ़ेगा। हमें इस बात का मुकाबला करने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि एकल परिवार और कामकाजी जोड़ों के बढ़ने के साथ तैयार और खाने को तैयार उत्पाद आधुनिक जीवनशैली का जरूरी हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा, पहले, हम घर पर पकनी और सॉस बनाते थे, लेकिन हमें ये चीजें तुरंत तैयार चाहिए। अगर कोई गलत कथानी बनाई जाती है, तो हम इस क्षेत्र के लिए वैसा विकास नहीं देख सकते जैसा हम सोचते हैं। पासवान ने कहा कि उनके मंत्रालय ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर एक संपत्ति बनाई है, जिसकी दूसरी बैठक में हाल ही में ऐसे संदेशों का मुकाबला करने के तरीकों पर चर्चा हुई। उन्होंने उद्योग जगत के अगुवा लोगों से इस मुद्दे की जिम्मेदारी लेने की अपील की।

कार्बन ट्रेडिंग मंच सितंबर तक चालू होने की संभावना

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के चेयरमैन घनश्याम प्रसाद ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में कार्बन ट्रेडिंग मंच सितंबर तक चालू होने की संभावना है। यह कदम नवीकरणीय ऊर्जा बदलाव को गति प्रदान करेगा। श्री प्रसाद यहां 'इंडिया एनर्जी' शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। बताया कि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का बड़ा लक्ष्य रखा है। इसको देखते हुए यह महत्वपूर्ण है। देश में बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) पर हस्ताक्षर की धीमी गति को देखते हुए यह नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक व्यवहारिक बनाने में भी सहायक हो सकता है। प्रसाद ने कहा, 'कार्बन ट्रेडिंग मंच सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और सितंबर तक इसके शुरू होने की पूरी संभावना है।

ट्रैफिक रूल तोड़े तो कटेंगे नम्बर निलम्बित होगा लाइसेंस

नई, दिल्ली, एजेंसी

सरकार सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और जिम्मेदारी से वाहन चलाने को बढ़ावा देने के लिए 'ग्रेड' आधारित ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है। इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंक काटे जाएंगे और गंभीर या बार-बार उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकेगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में हर वर्ष करीब 1.8 लाख लोगों की मौत मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए वाहन चलाने, तेज रफ्तार, गलत दिशा में जाने या नशे में गाड़ी चलाने जैसे कारणों से होती है।

राष्ट्रीय राजधानी में उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ

- जिम्मेदारी से वाहन चलाने को बढ़ावा देने को 'ग्रेड' आधारित ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली की तैयारी



(सीआईआई) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार सड़क सुरक्षा के लिए कई कदम उठा रही है। गडकरी ने बताया कि सरकार पहले ही यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ा चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन है।

उन्होंने कहा, हम ड्राइविंग लाइसेंस में 'ग्रेड अंक प्रणाली' ला रहे हैं। मंत्री ने समझाते हुए कहा कि यातायात उल्लंघन पर कुछ अंक काटे जाएंगे। यदि सभी अंक समाप्त हो जाते हैं तो दोषी का लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है या अपराध दोहराने पर रद्द भी किया जा सकता है। यह योजना जल्द ही शुरू की जाएगी। गडकरी ने कहा कि भारत में हर साल करीब पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और 1.8 लाख लोगों की जान जाती है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में से 72 प्रतिशत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोग हैं। 18 वर्ष से कम आयु के 10,119 लोगों की दुर्घटनाओं में जान गई। हेलमेट का उपयोग न करने से 54,122, सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने से 14,466 जबकि तेज रफ्तार के कारण 1.2 लाख लोगों की जान गई।

नो कॉस्ट ईएमआई के छिपे हुए खतरे और नुकसान



क्या नो कॉस्ट ईएमआई आपके लिए फायदेमंद है?

- यह आपके लिए सही हो सकता है यदि: जो समान आप नो कॉस्ट ईएमआई पर खरीद रहे हैं वो आप वैसे भी खरीदने ही वाले थे।
- नकद भुगतान करने पर कोई अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिल रहा हो।
- आप हर महीने समय पर किस्त चुकाने का अनुशासन रखते हों।
- प्रो टिप: पेमेट करने से पहले 'टोटल इफेक्टिव प्राइस' जरूर देखें। अगर किस्तों का कुल योग और प्रोसेसिंग फीस मिलाकर एमआरपी से ज्यादा है, तो वह 'नो कॉस्ट' नहीं है।

● डिस्काउंट का खेल (डिस्काउंट ऑफसेट) यह सबसे आम तरीका है। बैंक आपसे ब्याज लेता है, लेकिन रिटेलर उस ब्याज के बराबर की छूट आपको शुरू में ही दे देता है। इस तरह आपको कुछ अतिरिक्त पैसा जाता नहीं दीखता। उदाहरण: मान लीजिए आप 30,000 का फोन खरीदते हैं और उस पर ब्याज 3,000 है। चाल: दुकानदार फोन की कीमत 27,000 कर देगा। बैंक आपसे 27,000 लेगा और उस पर 3,000 ब्याज जोड़ेगा। आप अंत में 30,000 ही चुकाएंगे, लेकिन बैंक को उसका मुनाफा मिल गया।

● प्रोसेसिंग फीस का 'झटका' भले ही ब्याज 'माफ' दिख रहा हो, लेकिन लगभग हर नो कॉस्ट ईएमआई पर एक प्रोसेसिंग फीस लगती है। यह 199 से लेकर 1,000 तक हो सकती है। यह पैसा बैंक की सीधी कमाई है और यह कभी 'फ्री' नहीं होता।

● नकद छूट (कैश डिस्काउंट) का नुकसान अक्सर, अगर आप नकद या डेबिट कार्ड से पूरा भुगतान करते, तो आपको 5-10% की सीधी छूट मिल सकती थी। नो कॉस्ट ईएमआई चुनकर आप उस छूट को खो देते हैं, जिसका मतलब है कि वह सुविधा आपको महंगी पड़ी।

सोना तस्करी मामला: रान्या राव के खिलाफ ईडी ने दखिल की चार्जशीट

बेंगलुरु, एजेंसी

प्रवर्तन निदेशालय ने सोना तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव, उनके सहयोगी तरुण कोंडुरु और बल्लारी के स्वर्ण व्यापारी साहिल साकरिया जैन के खिलाफ बेंगलुरु की विशेष अदालत में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। जांच में सामने आया है कि मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच करीब 127.28 किलोग्राम विदेशी सोना अवैध रूप से भारत लाया गया। जौहरियों और बिचौलियों के नेटवर्क के जरिए इसे घरेलू बाजार में खपाया गया, जिसकी अनुमानित



कीमत 102.55 करोड़ है। शुरुआत 3 मार्च 2025 को हुई, जब राजस्व खुफिया निदेशालय ने दुबई से लौटी रान्या राव को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया। अभिनेत्री के पास से 14.213 किलो सोने की छड़े बरामद हुईं, बाद में उनके घर से 2.06 करोड़ के जेवर और 2.67 करोड़ की नकदी जब्त की गई।

भारी कमीशन और बार-बार यात्राएं

ईडी की जांच के अनुसार, रान्या राव ने तस्करी के लिए कई अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कीं। रिपोर्टों के मुताबिक, वह प्रति किलोग्राम सोने की तस्करी पर 4 से 5 लाख रुपये तक का कमीशन लेती थीं। इस मामले में CBI ने DR1 की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। मई 2025 में ED ने कर्नाटक के 16 स्थानों पर छापेमारी कर कई आपतिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और विदेशी मुद्रा भी बरामद की थी, जिन्हें अब सबूत के तौर पर चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है।

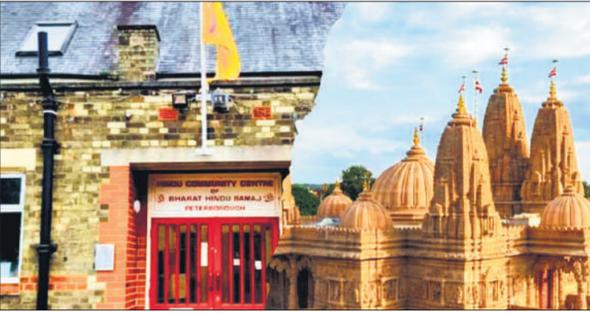
ब्रिटेन: 40 साल पुराने हिंदू मंदिर पर बंद होने का खतरा, काउंसिल के बिक्री के फैसले से आक्रोश

लंदन/पीटरबरो, एजेंसी।

पूर्वी ब्रिटेन के पीटरबरो शहर में स्थित 40 साल पुराने 'भारत हिंदू समाज मंदिर' और कम्युनिटी सेंटर पर बंद होने का काला साया मंडरा रहा है। स्थानीय पीटरबरो सिटी काउंसिल ने उस ऐतिहासिक भवन को बेचने का निर्णय लिया है, जिसमें यह मंदिर 1986 से संचालित है।

इस फैसले ने न केवल स्थानीय हिंदू समुदाय बल्कि ब्रिटेन की प्रमुख हिंदू संस्थाओं में भी भारी रोष पैदा कर दिया है। न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स स्थित इस मंदिर से कैम्ब्रिजशायर, नॉरफॉक और लिंकनशायर के लगभग 13,000 से अधिक हिंदू जुड़े हुए हैं। मंदिर प्रशासन का आरोप है कि काउंसिल ने यह फैसला बिना

• 1986 से संचालित है मंदिर, फैसले के बाद प्रमुख हिंदू संस्थाओं ने जताया रोष



किसी पारदर्शिता या समुदाय की सहमति के "बंद दरवाजों के पीछे" लिया है। आस्था और दशकों पुरानी विरासत से जुड़ा समुदाय का कहना है कि यह केवल एक

संपत्ति का मामला नहीं, बल्कि उनकी आस्था और दशकों पुरानी विरासत से जुड़ा सवाल है।

वर्ल्ड व्हीफ

अम्मान समझौते' के तहत 86 परिवारों को मिली आजादी

दमिश्क। सीरिया के दक्षिणी प्रांत स्वेदा में महीनों से जारी अशांति को शांत करने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। सीरियाई सरकार और सशस्त्र समूहों के बीच हुए 'अम्मान समझौते' के तहत कैदियों और बंधकों की अदला-बदली की प्रक्रिया गुरुवार को पूरी हो गई। इस मानवीय पहल के जरिए कुल 86 सीरियाई परिवारों को राहत मिली है। समझौते के तहत सशस्त्र समूहों ने आह्वान किया गए 25 नागरिकों को रिहा किया, जिसके जवाब में सीरियाई अधिकारियों ने हिरासत में लिए गए 61 बंदियों को छोड़ दिया। सीरियाई आंतरिक प्राधिकरण के प्रवक्ता नूरुद्दीन अल-बाबा ने इसे तनाव कम करने और शांतिपूर्ण मार्ग बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। हालांकि, अधिकारियों का मानना है कि क्षेत्र में स्थिरता के लिए अभी भी कई चुनौतियां बरकरार हैं।

आदिवासी महिला पर हमले के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन

सिलीगुड़ी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक गर्भवती आदिवासी महिला पर हमले के विरोध में गुरुवार को जमकर बवाल हुआ। जन्जाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने राज्य सचिवालय 'उत्तरकथा' के धरोवार की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस और वॉटर केन का इस्तेमाल करना पड़ा। 23 दिसंबर को फांसीदेवा में जमीन विवाद के दौरान एक गर्भवती महिला पर हमला हुआ था, जिसमें उसके अजन्मे शिशु की मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारी मुख्य आरोपी के लिए मृत्युदंड और फरार चार अन्य आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

अल कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान की याचिका पर सुनवाई करेगा

इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सजा के निलंबन की मांग को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और बुशारा बीबी की याचिका की सुनवाई 11 मार्च को करेगा। एक जवाबदेही अदालत ने 17 जनवरी 2025 को खान और बीबी को 19 करोड़ पाउंड के भ्रष्टाचार के मामले में क्रमशः 14 और सात साल की सजा सुनाई थी। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि दोनों ने इमरान के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ब्रिटेन से पाकिस्तान भेजे गये 50 अरब रुपए वधे बनाने के बदले अरबों रुपए और बहरीया टाउन में सैकड़ों कनाला जमीन शिफत के तौर पर ली थी। दोनों ने इसी सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया।

ट्रंप टैरिफ नहीं लगाते तो बेहतर होती अमेरिकी अर्थव्यवस्था : आईएमएफ

अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत, लेकिन शुल्क और बढ़ते कर्ज से जोखिम बरकरार : रिपोर्ट

वॉशिंगटन, एजेंसी

अमेरिकी अर्थव्यवस्था के इस वर्ष तेजी से बढ़ने के साथ ही बेरोजगारी में कमी आ सकती है। हालांकि, संघीय बजट घाटा और बढ़ता सरकारी कर्ज स्थिरता के लिए जोखिम बन सकता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने यह बात कही। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ यानी आयात शुल्क नहीं होते, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और बेहतर हो सकती थी।

आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का समग्र आकलन पेश किया है। 191 देशों के संगठन का विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में आकलन मोटे तौर पर सकारात्मक है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) यानी वस्तुओं एवं



सेवाओं का कुल उत्पादन 2026 की चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 2.4 प्रतिशत बढ़ सकता है। यह वृद्धि 2025 में दर्ज 2.2 प्रतिशत की दर से अधिक होगी।

आईएमएफ का अनुमान है कि अमेरिका में बेरोजगारी दर 2025 के अंत में 4.5 प्रतिशत से घटकर 2026 में 4.1 प्रतिशत रह जाएगी। वहीं, महंगाई दर 2027 तक अमेरिकी केंद्रीय बैंक के दो प्रतिशत के लक्ष्य तक आ सकती है। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि फेडरल रिजर्व रेपो दर को मौजूदा 3.6 प्रतिशत से दर को घटाकर लगभग 3.4 प्रतिशत तक ला सकता है। इसने 2025 में नीतिगत ब्याज दर में तीन बार कटौती की

ट्रंप के टैरिफ पर और भी हैं तीखी प्रतिक्रियाएं

यूरोपीय संघ (EU): 'डील इज ए डील'

समझौते पर संकट: यूरोपीय संघ ने कहा है कि एक बार हुआ समझौता बदला नहीं जाना चाहिए। ईयू ने अगस्त 2025 में हुए उस व्यापार समझौते के भविष्य पर सवाल उठाए हैं, जिसमें शुल्क को 15% की सीमा तक सीमित रखने की बात थी। यूरोपीय संसद ने इस नई अनिश्चितता के विरोध में अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील के अनुसमर्थन पर फिलहाल रोक लगा दी है।

थी। उन्होंने हालांकि आगाह किया कि अमेरिकी रोजगार बाजार में 'अत्यधिक गिरावट' आने की स्थिति को छोड़कर, सरकार को और अधिक कटौती करने से बचना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका को मजबूत उत्पादकता वृद्धि का लाभ मिला है। आईएमएफ ने चेताया कि संरक्षणवादी व्यापार नीतियां

चीन: 'व्यापार युद्ध में कोई विजेता नहीं'

चीन ने ट्रंप के शुल्कों को आर्थिक दादागिरी" करार दिया है। इससे पहले 2025 में जब अमेरिका ने भारी शुल्क लगाए थे, तो चीन ने भी अमेरिकी कोयले, एलएनजी (LNG) और कच्चे तेल पर 10% से 15% का जवाबी शुल्क लगाकर पालटवार किया था। चीन ने दुर्लभ मृदा धातुओं के निर्यात पर नियंत्रण कड़ा कर दिया है, जो अमेरिकी चिप और हथियार उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है।

अपेक्षा से अधिक आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं। आईएमएफ ने संघीय सरकार के बढ़ते कर्ज को भी चिंता जताई। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका का सार्वजनिक कर्ज जीडीपी के अनुपात में पिछले वर्ष के लगभग 100 प्रतिशत से बढ़कर 2031 तक करीब 110 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

इतिहास सही पढ़ाते तो औरंगजेब नायक नहीं बनता: फडणवीस

मुंबई, एजेंसी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर पिछले 70 साल के दौरान स्कूलों में इतिहास को सही ढंग से पढ़ाया जाता, तो कोई भी मुसलमान मुगल बादशाह औरंगजेब को नायक नहीं मानता। उन्होंने मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच तुलना करने के प्रयासों की भी निंदा की।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही। फडणवीस ने कहा कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में पहले मुगलों पर 17 पृष्ठ और शिवाजी महाराज पर केवल एक पृष्ठ था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अब शिवाजी महाराज



और मराठा इतिहास के लिए 20 पृष्ठ सुनिश्चित किये हैं। औरंगजेब को नायक मानने वालों का धैर्य विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह टीपू सुल्तान के अच्छे या बुरे होने की बहस में नहीं पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि, हम टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज की किसी भी तरह की तुलना का विरोध करेंगे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने ऐसा अपने राज्य को बचाने के लिए किया। लेकिन उन्होंने 75,000 हिंदुओं और 33,000 नायर को भी मार डाला।

परमाणु वार्ता: युद्ध की आहट के बीच जिनेवा में कूटनीति का अंतिम अवसर

जिनेवा, एजेंसी

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और तेहरान के बीच गुरुवार को जिनेवा में तीसरे दौर की उच्चस्तरीय वार्ता हुई। इसे कूटनीति का आखिरी मौका माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ टेबल पर बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए पश्चिम एशिया में युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों का भारी बेड़ा तैनात कर दिया है।

पिछले साल जून के बाद से दोनों देशों के बीच यह तीसरे दौर की सीधी बातचीत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वार्ता के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त सीमाएं थोपना चाहते हैं। वाशिंगटन का मानना है कि ईरान के भीतर बढ़ता नागरिक असंतोष और हालिया विरोध प्रदर्शन तेहरान को समझौते

'विनाशकारी होगा युद्ध': ईरान

दूसरी ओर, ईरान अपने रुख पर अडिग है। तेहरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह यूरेनियम संवर्धन (Uranium Enrichment) के अपने अधिकार को नहीं छोड़ेगा। जिनेवा रवाना होने से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका हमला करता है, तो पश्चिम एशिया में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डे उनके निशाने पर होंगे। कहा कि यह युद्ध किसी की जीत नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए 'विनाशकारी' होगा। अराघची ने एक साक्षात्कार में कहा कि चुंकि अमेरिकी सैन्य ठिकाने पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैले हुए हैं, फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें जिनेवा वार्ता पर टिकी हैं, क्योंकि यहां से निकलने वाला निष्कर्ष तय करेगा कि क्षेत्र शांति की ओर बढ़ेगा या एक बड़े सैन्य संघर्ष की ओर।

की मेज पर झुकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अमेरिकी रक्षा सूत्रों के अनुसार, सैन्य तैनाती का

109 साल बाद ब्रिटिश सरकार से युद्ध ऋण पर करोड़ों का दावा

सीहोर। मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर के प्रसिद्ध दिवांत व्यवसायी सेठ जुम्मा लाल रूठिया के पोते विवेक रूठिया ने दावा किया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उनके दादा से 35,000 रुपये का 'युद्ध ऋण' लिया था, जो आज तक नहीं लौटाया गया। अब परिवार इस राशि को वसूली के लिए ब्रिटेन सरकार को कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है।

65 वर्षीय विवेक रूठिया के अनुसार, साल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) के समय ब्रिटिश प्रशासन ने युद्ध प्रयासों के लिए स्थानीय धनाढ्य नागरिकों से आर्थिक सहायता मांगी थी। उन्हें अपने दादा की वसीयत में कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज मिले हैं, जिनमें ब्रिटिश सरकार के साथ हुए इस लेनदेन का स्पष्ट उल्लेख है। विवेक रूठिया ने 4 जून, 1917 को भोपाल में ब्रिटिश 'पॉलिटेकनल एजेंट' द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र पेश किया है। इसमें लिखा है— "सेठ जुम्मा लाल ने भारतीय युद्ध ऋण के लिए 35,000 रुपये दिए और इस तरह सरकार एवं साम्राज्य के प्रति अपनी वफादारी दिखाई।

पश्चिम बंगाल चुनाव जीतेगी भाजपा, हर घुसपैठिये को बाहर निकालेंगे : शाह

अररिया (बिहार), एजेंसी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को विश्वास जताया कि भाजपा आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतेगी और राज्य से हर एक घुसपैठिये को बाहर निकालेगी। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकीय बदलाव से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में पश्चिम बंगाल शामिल है। शाह ने यह बात बिहार के अररिया जिले में कही, जहां उन्होंने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 175 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और दो नए सीमा चौकियों को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि देश से हर एक घुसपैठिये को बाहर निकालना भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कहा कि ये लोग न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि गरीबों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उनके प्रभाव को भी कम करते हैं। शाह ने कहा कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ से सीमावर्ती इलाकों में अतिक्रमण भी बढ़ता है और इसे हटाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ जनसांख्यिकीय बदलाव का घुसपैठ भी पैदा करती है, जो किसी क्षेत्र की संस्कृति और यहां तक कि उसकी भौगोलिक स्थिति को भी

'टैक्सपेयर्स के पैसे' का हवाला

लेबर पार्टी के नेतृत्व वाली पीटरबरो सिटी काउंसिल ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा है कि संपत्ति की बिक्री से करदाताओं (Taxpayers) के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल्य सुनिश्चित करना उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। काउंसिल कैबिनेट की बैठक में तर्क दिया गया कि वित्तीय घाटे को कम करने के लिए सार्वजनिक संपत्तियों का उचित मूल्य पर बेचना आवश्यक है।

हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा

वहीं, हिंदू काउंसिल यूके ने काउंसिल के इस कदम को कड़ी निंदा की है। संस्था ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने मंदिर के "सामाजिक प्रभाव" और इसके स्वामित्व को समुदाय को हस्तांतरित करने की पूर्ण प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। मंदिर समिति अब इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई और सार्वजनिक अभियान चलाने की तैयारी कर रही है ताकि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बेधर होने से बचाया जा सके।

संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर स्थिति सुधारने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का होगा गठन



प्रभावित कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनसांख्यिकीय बदलाव का अध्ययन करने और सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर स्थिति सुधारने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जनसांख्यिकीय बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं। शाह ने कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत बिहार के सीमांचल क्षेत्र से होगी, जहां वे कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव के दौरान चार दिन तक रुके थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आलोचना के बावजूद भाजपा ने बिहार चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने में एसएसबी की अहम भूमिका है।

कैसा रहेगा आपका आज का दिन	
	आज आपको अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में विरोधी परेशान करेंगे। सहकर्मी आपकी सहायता करेंगे।
	आज अनावश्यक यात्रा न करें। सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होना पड़ सकता है। अति आत्मविश्वास के कारण काम बिगड़ सकता है।
	आज ससुरारों से संपर्क बढ़ेगा। विभिन्न व्यवहार के कारण व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी।
	आज आपका काम में मन नहीं लगेगा। अनावश्यक विचारों से स्वयं को बचाएं। शांत और धैर्यवान होकर समस्या का समाधान खोजें।
	आज व्यवसाय में वृद्धि के लिए निवेश कर सकते हैं। एक प्राकृतिक होकर अपने काम पर ध्यान दें। शाम को कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
	आज दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। व्यापार में बड़ी खाड़ेदारी होगी। शरीर में थकवट व ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे।
	आज राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद प्राप्त हो सकता है। अधिकारिण आपकी विचारों को तबज्जो देंगे।
	आज व्यवसाय में धन लाभ हो सकता है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
	आज कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व कम होगा। कानूनी पदचढ़ाई में धिरेने की आशंका है। कोई नया काम शुरू न करें।
	आज कारोबार में नव प्रयोग करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। छात्रों को बड़ी सफलता मिलने के योग्य मान रहे हैं। आपकी योजना पूर्ण होगी।

रेलवे में डिजिटल क्रांति

ऑनलाइन कर सकेंगे रेल हादसों व सामान चोरी के दावों का निपटारा

नई दिल्ली। एजेंसी

रेल यात्रियों के लिए अब ट्रेन हादसों, अनहोनी घटनाओं या सामान के नुकसान और चोरी के मामलों में क्षतिपूर्ति का दावा करना बेहद आसान होने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना '52 हफ्तों में 52 सुधार' के तहत तीसरे और चौथे बड़े सुधार के रूप में 'ई-आरसीटी' (e-RCT) और 'रेलटेक नीति' की घोषणा की। इस नई डिजिटल प्रणाली के माध्यम से कोई भी पीड़ित यात्री देश के किसी भी कोने से रेलवे दावा न्यायाधिकरण (आरसीटी) के समक्ष ऑनलाइन अपना दावा

पेश कर सकेगा। अब तक यात्रियों को दावा फाइल करने के लिए सही क्षेत्राधिकार चुनने और भौतिक रूप से न्यायाधिकरण के दफ्तरों के चक्कर काटने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, विशेषकर उन यात्रियों के लिए जो अपने गृह राज्य से दूर यात्रा कर रहे हों, लेकिन अब ई-आरसीटी प्रणाली इन बाधाओं को पूरी तरह खत्म कर देगी। रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि अगले 12 महीनों के भीतर देश भर में मौजूद रेलवे दावा न्यायाधिकरण की सभी 23 पीठों को पूरी तरह डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। ई-फाइलिंग से लेकर मामले की सूचना प्रणाली तक की पूरी प्रक्रिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)



पर आधारित होगी, जिससे न्यायिक निर्णयों की गति में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। वैष्णव ने कहा कि यदि यह डिजिटल मॉडल सफल रहता है, तो इसी तरह के समाधान भविष्य में केंद्रीय तथासैनिक न्यायाधिकरण जैसे अन्य निकायों में भी लागू किए

वकीलों और दफ्तरों के चक्करों से मुक्ति

पुराने सिस्टम में यात्रियों और वकीलों को दस्तावेज जमा करने और केस की प्रगति देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से न्यायाधिकरण के दफ्तर जाना पड़ता था। नई डिजिटल व्यवस्था के तहत कहीं से भी आवेदन: यात्री अपने घर या गंतव्य स्टेशन से ही इलेक्ट्रॉनिक

जा सकते हैं। अब यात्रियों और उनके वकीलों को दस्तावेज जमा करने या केस को ट्रैक करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे अपने स्थान की परवाह किए बिना कहीं भी ऑनलाइन मामले दर्ज कर सकेंगे और उसकी प्रगति देख सकेंगे इसके साथ ही, रेलवे

तरीके से दावा फाइल कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित होगी, जिससे न्यायिक निर्णय लेने की गति तेज होगी। केस फाइलिंग से लेकर अंतिम फैसले तक की पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी।

में अत्याधुनिक तकनीक को व्यवस्थित तरीके से शामिल करने के लिए 'रेलटेक नीति' को भी मंजूरी दी गई है। यह नई नीति रक्षा क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के स्टार्टअप ढांचे और टेलीकॉम नवाचार नीति जैसे सफल मॉडलों का अध्ययन करने के बाद तैयार की गई है। इस

नीति का मुख्य उद्देश्य पुराने और जटिल टेकेदारी सिस्टम को हटाकर एक ऐसा नवाचार-संचालित ढांचा तैयार करना है, जहां स्टार्टअप्स, शोधकर्ता और इनोवेटर्स भारतीय रेलवे के साथ आसानी से जुड़ सकें।

अब कोई भी व्यक्ति जिसके पास रेलवे के लिए कोई मजबूत तकनीकी आईडिया हो, वह एक समर्पित 'रेलटेक पोर्टल' के जरिए सीधे संपर्क कर सकेगा। यह पोर्टल पूरी तरह डिजिटल होगा और नई तकनीक के परीक्षण व उसे अपनाने की प्रक्रिया को बेहद सरल बना देगा, जिससे भारतीय रेलवे को वैश्विक स्तर की आधुनिक तकनीक से लैस करने में मदद मिलेगी।

आज का पंचांग		सुअेक - 73 का हल	
श. 12	म. 10	6	1
1	9	3	5
2	8	2	8
3	7	4	6
4	6	5	9
5	5	3	7
6	4	2	8
7	3	1	9
8	2	9	6
9	1	8	5
10	0	7	4
11	9	6	3
12	8	5	2
13	7	4	1
14	6	3	0
15	5	2	9
16	4	1	8
17	3	0	7
18	2	9	6
19	1	8	5
20	0	7	4
21	9	6	3
22	8	5	2
23	7	4	1
24	6	3	0
25	5	2	9
26	4	1	8
27	3	0	7
28	2	9	6
29	1	8	5
30	0	7	4

